खण्ड-06 सत्र -06 (भाग-01) अंक-60

सोमवार

09 अक्तूबर 2017
17 अश्विन, 1939 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

छठा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06 (भाग-01) में अंक 59 से अंक 62 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

विषय सूची

सत्र–6 (भाग–01) सोमवार, 09 अक्तूबर, 2017 / 17 अश्विन, 1939 (शक) अंक–60

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	निधन संबंधी उल्लेख	3–4
3.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	4–15
4.	सरकारी संकल्प (नियम–90) पर चर्चाः दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा किराया बढ़ाये जाने पर	16–89
5.	उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य	90–118

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–6 (भाग–01) सोमवार, 09 अक्तूबर, 2017 / 17 अश्विन, 1939 (शक) अंक–60

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री सुखवीर सिंह दलाल
7. श्री ऋतुराज गोविन्द
8. श्री संदीप कुमार
9. श्री रघुविन्द्र शौकीन
10. श्रीमती बंदना कुमारी
11. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
12. श्री राजेश गुप्ता
13. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
14. श्री सोमदत्त
15. सुश्री अलका लाम्बा
16. श्री आसिम अहमद खान
17. श्री विशेष रवि
18. श्री हजारी लाल चौहान

19. श्री शिव चरण गोयल
20. श्री गिरीश सोनी
21. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
22. श्री राजेश ऋषि
23. श्री महेन्द्र यादव
24. श्री नरेश बाल्यान
25. श्री आदर्श शास्त्री
26. श्री गुलाब सिंह
27. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
28. सुश्री भावना गौड़
29. श्री सुरेन्द्र सिंह
30. श्री विजेन्द्र गर्ग
31. श्री प्रवीण कुमार
32. श्री मदन लाल
33. श्री सोमनाथ भारती
34. श्रीमती प्रोमिला टोकस
35. श्री नरेश यादव
36. श्री करतार सिंह तंवर
37. श्री अजय दत्त
38. श्री दिनेश मोहनिया
39. श्री सौरभ भारद्वाज
40. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
41. श्री सही राम
42. श्री नारायण दत्त शर्मा
43. श्री राजू धिंगान
44. श्री मनोज कुमार
45. श्री नितिन त्यागी
46. श्री ओमप्रकाश शर्मा
47. श्री एस.के. बग्गा
48. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
49. मो. इशराक
50. श्री श्रीदत्त शर्मा
51. चौ. फतेह सिंह
52. श्री जगदीश प्रधान
53. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–6 (भाग–01) सोमवार, 09 अक्तूबर, 2017 / 17 अश्विन, 1939 (शक) अंक–60

सदन अपराह्न 2.11 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

शोक संवेदना

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य गण ये अत्यंत दुख का विषय है कि दिल्ली विधान सभा के पूर्व विधायक श्री राजेन्द्र गुप्ता जी का दिनांक 7 अक्टूबर, 2017 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे पहली दिल्ली विधान सभा 1993 से 1998 में तिमारपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1965 में राजनीति में आए। पहली बार वर्ष 1977 में दिल्ली नगर निगम के सदस्य निर्वाचित हुए तत्पश्चात दूसरी बार वर्ष 1983 में उन्होंने दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीता तथा उन्होंने निगम की स्थाई समिति, पदोन्नति नियुक्ति समिति, दिल्ली जल मल प्रदाय समिति और शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रूचि थी। जन–प्रतिनिधि के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को सदन में उठाया तथा उनके समाधान का यथा संभव प्रयास किया। मैं श्री राजेन्द्र गुप्ता के निधन पर गहन शोक व्यक्त करता हूं तथा अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्य गण, ये अत्यंत दुःख का विषय है कि दिनांक 6 अक्टूबर, 2017 को अरूणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारतीय वायु सेना का हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से सात सैन्य कर्मियों की मौत हो गई थी जिनमें पाँच वायु सेना के कर्मचारी थे और दो सैन्य कर्मी थे। इस तरह की गंभीर क्षति चिंता का विषय है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले जवानों के प्रति शोक प्रकट करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब हम सभी सदस्य खड़े होकर दिवगंत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट के लिए मौन धारण करेंगे।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन)

अध्यक्ष महोदयः ओम शांति शांति शांति।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्ष महोदयः किस बात को लेकर? क्या हो गया ऐसा?

श्री ओम प्रकाश शर्माः बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की मीटिंग के बगैर जो एजेंडा बन रहा है ये संविधान और डेमोक्रेसी दोनों के खिलाफ है,

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ऐसा कहीं नहीं है। मैंने संविधान देख लिया। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बैठिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: क्या है, आप बता दीजिए क्या है?

अध्यक्ष महोदयः ऐसा नहीं है। मैंने देख लिया।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: तो आप बता दीजिए ना, क्या है?

अध्यक्ष महोदयः मैं बता रहा हूं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: तो फिर क्या है? .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए, मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण....

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा: तो इस विषय पर आपने कुछ, कोई अपना वक्तव्य देना, कुछ बताना...

अध्यक्ष महोदयः मैंने बताया, मैंने देख लिया ,ऐसा कहीं कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: नहीं, तो बीएसी की मीटिंग नहीं हो रही है

अध्यक्ष महोदयः आपको कुछ देना है, इस पर लिखित में दे दीजिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: नहीं, लिखकर क्या, मैं तो पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः हां, मैंने बताया ना, ओम प्रकाश जी, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि आवश्यक है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की मीटिंग।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा: हां, मैं हूं ना जी...

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि बहुत आवश्यक है।

श्री ओम प्रकाश शर्माः नहीं–नहीं, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी के बगैर एजेंडा बन रहा है क्या सदन का?

अध्यक्ष महोदयः एजेंडा बना कहां है, एजेंडा तो कोई विशेष है नहीं।

श्री ओम प्रकाश शर्माः तो फिर बिना एजेंडे के जो अभी तीन दिन पहले और आज जो मीटिंग हो रही है, बिना एजेंडे के मीटिंग है ये।

अध्यक्ष महोदयः ऐसा है आपको सर्व हुआ है ना। आपको जो भी बिजनेस है, वो सर्व हो गया ना?

श्री ओम प्रकाश शर्माः नहीं, सर्व हो गया। मैं पूछ रहा हूं बिना बीएसी.

अध्यक्ष महोदयः बस ठीक है, बैठिये अब। बैठिये, ओम प्रकाश जी प्लीज।

श्री ओम प्रकाश शर्माः बिना बीएसी के क्या आपने खुद अपने आप कर लिया है वो?

अध्यक्ष महोदयः मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम 54 के अंतर्गत

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः मुझे समझ नहीं आ रही ये डमोक्रेटिक सेटअप में जो काम होना चाहिए....

अध्यक्ष महोदयः देखिए विजेन्द्र जी, इन्होंने परसों भी ये बात,

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, कोई आवश्यक नहीं है कि बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की मीटिंग बुलवाई जाए, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की मीटिंग हर बार बुलवाई जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बुलाई ही नहीं जाती यहां तो। आप बताएं ना, 15 मीटिंग्स हो चुकी, कब बुलाया है?

अध्यक्ष महोदयः किसको?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हमारे मैम्बर को?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, एडवाइजरी कमिटी की मीटिंग में बुलाते थे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हुई थी ना?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, ऐसा नहीं, नहीं हुई है। ये उस वक्त ये सदन से बाहर थे।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं तो कह रहा हूं आपका नोटिस तो निकला होगा.

अध्यक्ष महोदयः ये उस वक्त सदन से बाहर थे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उनके बाहर हो जाने के बावजूद भी बीएसी हो सकती है ....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदयः नहीं, हुई है।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, नोटिस तो निकला होगा ना बिजनेस एडवाइजरी कमिटी का?

अध्यक्ष महोदयः अगर आपको कुछ डाउट है, वो मैं दिखा दूंगा। आप आ जाइयेगा।

श्री ओम प्रकाश शर्माः ये अनडमोक्रेटिक है जो आप कर रहे है।

अध्यक्ष महोदयः देखिए, अगर सदन में इसी ढंग से विषय उठने हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं कह रहा हूं आप आ जाइयेगा, मैं दिखा दूंगा हुई हैं या नहीं हुई हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मेरे कक्ष में आ जाइयेगा जो एडवाइजरी कमिटी की मीटिंग हुई हैं, जितनी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जितनी आपकी एब्सेंस में, मैं दिखा दूंगा।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः सदन की क्या जरूरत है जब सारे आपके उसके होने हैं तो, ... (व्यवधान)

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, दूसरा विषय हम आपको ये बताना चाहते हैं जो पिछले सदन में जिस तरह की अमर्यादित भाषा के ऊपर मुख्यमंत्री ने हमारी मां तक को गाली निकाली, उसका हमने आपको अभी भी लिखित में दिया। हम चाहते हैं कि आप उसके ऊपर बताएं कि क्या मुख्यमंत्री आज उसके ऊपर माफी मांग रहे है?

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, आपने एक सैकेंड विजेन्द्र जी, या तो मैं सिरसा जी की बात का उत्तर दे लूं,

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः त्रिपाठी जी, अखिलेश जी,

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः झा साहब दो मिनट बैठिए। अखिलेश जी, बैठिए एक बार प्लीज। अखिलेश जी, झा साहब बैठिए दो मिनट बैठिए प्लीज। सिरसा जी, एक सैंकेड, मेरा ये कहना है इस पर आपने अभी 5 मिनट पहले मुझे दिया है। ठीक है। उस पर चर्चा कर सकूं, बात कर सकूं उसका समय नहीं मिला, एक बात। बात नंबर दो, इस सब पर जो चीज सदन में हुई है, उस पर चर्चा होने से पहले अगर कोई मन में दिक्कत थी, कोई बात थी... विजेन्द्र जी सारा मीडिया में जा चुका है,

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब छोड़िए।

... (व्यवधान)

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः तो मीडिया में जो जाएगा ही। मुख्यमंत्री गाली निकाले, ... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मुख्यमंत्री मां–बहन की गाली बकेंगे यहां पर?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ठीक है बोल लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मां–बहन की गाली देंगे यहां पर, क्या मतलब है?

... (व्यवधान)

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः अरे मां को गाली निकालेगे मुख्यमंत्री! अरे मां को! ये विपक्ष की मां को गाली है। अध्यक्ष जी, मेरे अकेले को नहीं है। ये सारे दिल्ली के विपक्ष को मां की गाली है। क्या एक औरत की गरिमा इस हाउस...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं। बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बोल लीजिए, जितना मर्जी आए, बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः एक औरत की गरिमा को आप हाउस के अंदर तार–तार करेंगे और फिर माफी भी नहीं मांगेगे!

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा हूं।

... (व्यवधान)

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, औरत की गरिमा का विषय है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब मीडिया में जा चुका है। आप फेसबुक पर उससे भी गंदा लिख चुके हैं। सब कुछ कर चुके हो, और फिर बात कर रहे है।

... (व्यवधान)

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः फेसबुक की बात नहीं हो रही, यहां पर हाउस...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः यहां पर हाउस की बात हो रही है।

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः अध्यक्ष महोदय, हर बार सदन के काम में ये लोग बाधा डालते है। सर, आप इन लोगों को बाहर निकाल दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः आप इस विधान सभा के अध्यक्ष हैं। आपके होते अगर ऐसा हुआ है तो आपके संज्ञान में लेना है।.

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, सदन का काम सदन में होगा। क्या आपने संज्ञान लिया इसमें, आपने संज्ञान लिया क्या? आपने क्या संज्ञान लिया इसके ऊपर?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी प्रकार से एलाउ नहीं कर रहा। ये तरीका ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये रास्ता ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं एलाउ नहीं कर रहा किसी को भी। बैठिए प्लीज। सिरसा जी, मैं कोई एलाउ नहीं कर रहा। ओम प्रकाश जी बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये माईक बंद करिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माईक बंद कर दीजिए सबका।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आज राज्यपाल पर चर्चा नहीं चाहते आप?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हम चाहते है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं चाहते राज्यपाल पर?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः इसका मतलब राज्यपाल पर चर्चा नहीं चाहते आप?

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कार्यवाही में से तो निकलवाइये?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, राज्यपाल के लेटर पर चर्चा नहीं चाहते आप?

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कार्यवाही में से निकलवाइये? ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नही, राज्यपाल के लेटर पर चर्चा नहीं चाहते आप?

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, ये गंभीर मामला...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मुझे बता दीजिए। उपराज्यपाल के लेटर पर आप चर्चा नहीं चाहते है?

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये गंभीर मामला है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप उप राज्यपाल के लैटर पर चर्चा नहीं चाहते। नहीं, मैं माईक किसी का अलाउ नहीं कर रहा हूं। आप बंद करिये। माइक

क्यों खोल रहे हैं? सबके बंद कर दीजिए। सबके माइक बंद रखिए। बोलिए, बोलिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया बैठ जाएं। नितिन जी, बैठिए, प्लीज बैठिए। बैठिए, सिरसा जी, बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः श्री केजरीवाल जी ने अभद्र भाषा बोली।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, मुझे एक बार बोलने दीजिए, प्लीज। बैठिए दो मिनट, झा साहब, बैठिए, प्लीज। त्रिपाठी जी, बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, बैठिए, जनरैल जी, बैठिए। त्रिपाठी जी, बैठिए, प्लीज, बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए, जरा प्लीज, बैठिए, झा साहब बैठिए, जरा बैठिए। जनरैल जी, बैठिए, प्लीज बैठिए। नितिन जी बैठिए प्लीज। जनरैल जी बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठिए। प्लीज, कमांडो जी।

मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम– 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। विजेन्द्र जी, सिरसा जी, या तो उनकी सुनूं या आपकी। दो में से मैं एक की सुन लूं। अच्छा बैठिए, विजेन्द्र जी ने कहा रूलिंग, तो दीजिए, विजेन्द्र जी ने कहा, रूलिंग दीजिए। दो मिनट बैठिए आप। दो मिनट बैठिए आप, बैठिए आप। अवतार जी, बैठिए प्लीज, बैठिए। मुझे

जैसा अभी कहा विजेन्द्र जी, मुझे 5 मिनट पहले आपका लैटर मिला, बैल बज रही थी, आप आए, चारों सदस्य आए। दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मुझे पत्र मिला, मैंने उसी वक्त कहा, मैं इस पर देखता हूं, क्या हो सकता है। एक बात, बात नम्बर दो, उस पत्र में कहीं पर भी आपने ये नहीं लिखा। ये आफ्टर थॉट है कि इसको कार्यवाही से बाहर निकलवा दिया जाए। नहीं, विजेन्द्र जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं, ओम प्रकाश जी, बैठ जाइए आप। ऐसे नहीं चलेगा। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप बाद में सोच–सोच के आएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। संशोधित या तो पत्र दीजिए या संशोधन कीजिए। मैं पूरा पढ़ चूका हूं, बैठ जाइए आप। सिरसा जी, आप जितना कह रहे हैं, आप उस वक्त सदन में नहीं थे जब मुख्यमंत्री जी का भाषण हो रहा था, आप सदन में नहीं थे उस वक्त। मैं फिर संज्ञान में ले रहा हूं, मैं जानकारी ले चूका हूं पूरी, आप सदन में नहीं थे बैठ जाइए, बैठिए।

मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम–54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई है, माननीय श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष ने भी नियम–66 के तहत अवमानना का नोटिस दिया है। आज सरकारी संकल्प पर चर्चा सूचीबद्ध है तथा माननीय उप राज्यपाल महोदय के संदेश पर भी सदन द्वारा विचार किया जाना है। सदन के समय के अधिकतम सदुपयोग के लिए आज कार्यसूची में सूचिबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी सूचना को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। श्री कैलाश गहलोत। देखिए, दिल्ली की जनता इस वक्त इतनी परेशान है, दिल्ली की जनता।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइए आराम से। आप नहीं चाहते दिल्ली की जनता पर चर्चा हो, आप नहीं चाहते दिल्ली की जनता पर चर्चा हो, दिल्ली की जनता पर तलवार लटका रखी है, मैट्रो के किराए के बढ़ाने की, आप नहीं चाहते।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, सोमनाथ जी, एक बार बात सुन लीजिए। सोमनाथ जी, विपक्ष नहीं चाहता, मैट्रो किराए की जो तलवार लटक रही है, दिल्ली की जनता पर, कल जिसका निर्णय हो रहा है, विपक्ष नहीं चाहता, उस पर चर्चा हो। आप उसमें भागीदार मत बनिए, उस पर चर्चा करिए। वो उस चर्चा को, उस चर्चा को हटाना चाहते हैं आज और इसलिए विघ्न डाल रहे हैं। दिल्ली की जनता मैट्रो के किराए से परेशान है। बैठिए, कल जिस पर मैट्रो निर्णय लेने जा रही है, आज उस पर चर्चा हो रही है, विपक्ष नहीं चाहता उस पर चर्चा हो। जगदीप जी, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, उनको बोलने दीजिए, हाँ, बोलने दीजिए। आप बैठिए, जो मर्जी आए बोलने दीजिए उनको।

... (व्यवधान)

सरकारी संकल्प पर चर्चा (नियम–90)

अध्यक्ष महोदयः माननीय परिवहन मंत्री द्वारा दिनांक 4 अक्तूबर, 2017 को

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, इतना गंभीर नहीं है, मैंने देख लिया, इतना गम्भीर नहीं है। अब श्री कैलाश गहलोत जी, माननीय परिवहन मंत्री द्वारा दिनांक

4 अक्तूबर, 2017 को नियम–90 के तहत प्रस्तुत सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः इस चर्चा में श्री अनिल बाजपेयी जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अनिल जी, आप शुरू कीजिए, क्या इन्तजार कर रहे हैं? आप शुरू करिए अपनी बात।

श्री अनिल बाजपेयीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मैट्रो ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। अरे! प्लीज सर, बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बाजपेयी जी, आप बोलिए, उनसे बात मत करिए। आपकी बात रिकार्ड हो रही है सारी, आप अपना रखिए।

श्री अनिल बाजपेयीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कल दिल्ली में बढ़ाए जा रहे मेट्रो के किराए की ओर दिलाना चाहता हूं। आज पूरी दिल्ली के अन्दर मेट्रो के किराए बढ़ाए जाने पर जनता में असंतोष है। आज जनता त्राहि–त्राहि कर रही है और ये भाजपा के लोग नहीं बात करने दे रहे हैं हाउस के अन्दर। अरे! बात करने दीजिए आप।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आप अगर ऐसे करेंगे, ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे निर्णय लेना

पड़ेगा मुझे मजबूरन निर्णय लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आप चर्चा में भाग लें। आप मेट्रो के किराए की चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और ये इस ढंग से बात करेंगे! बाजपेयी जी, आप अपनी बात रखिए।

श्री अनिल बाजपेयी: ये भाजपा के लोग सदन में ये बात नहीं रखने देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: बाजपेयी जी, आप मेट्रो पर चर्चा में... आप मेट्रो पर चर्चा शुरू करें। आप बोलने दीजिए उनको, आप मेट्रो पर चर्चा शुरू करें।

श्री अनिल बाजपेयी: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली में बढ़े हुए मेट्रो के किराए की ओर दिलाना चाहता हूं। आज पूरी दिल्ली के अन्दर मेट्रो के बढ़ते हुए किराए पर हा–हाकार मचा हुआ है, चाहे छोटा वर्ग हो या मीडियम क्लास लोग हों या बड़े घर के लोग हैं, सब लोगों में त्राहि–त्राहि मची हुई है। अरे! बात करने दीजिए भाई साहब! आज सर, मैं एक बात बताना चाहता हूं आज पूरी दिल्ली के अन्दर हमारे मुख्यमंत्री एक ऐसे हैं, जिन्होंने मेट्रो के लिए आवाज उठाई है। आपके नेता नरेन्द्र मोदी जो केन्द्र में बैठे हैं, कोई आवाज नहीं उठाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: बोलने दीजिए उनको, आप बैठिए प्लीज।

श्री अनिल बाजपेयी: मैं एक बात और कह देना चाहता हूं सर, आज ये देखिए आज सारे अखबारों में सारे मीडिया के लोग यहां खड़े हुए हैं। यहां सारे मीडिया के लोग बैठे हैं। आपका परिवार भी है, आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं। आप लोग हैं जो मेट्रो का किराया आप 10 रूपये देकर आते थे, आज 20 रूपये आप लोगों को किराया देना पड़ रहा है, निन्दा करनी चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी उनको देखिए। आज केन्द्र सरकार ये कहती है कि 3000 करोड़ रूपये दें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है

1500 करोड़ रूपये हम देंगे, आप करिए तो सही। लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं हैं ये लोग और एक और बात कह देना चाहते हैं सर, ये कागज है, ये आप देखिए किराए की जो हाइक है, 100 परसेंट इन लोगों ने कर दिए हैं। सर ढ़ाई किलोमीटर पर किराया पहले 11 रूपये था, आज बीस रूपये कर दिया गया है। 82 परसेंट! और कलकत्ते के अन्दर 5 रूपये हैं केवल, ये देखिए। आज 5 से 12 कि.मी. पर 15 रूपये किराया था। आज 30 रूपये किराया कर दिया गया है। सौ परसैंट किराया बढ़ा दिया गया यहां पर। आज 12 से 21 कि.मी. में 19 रूपये आपको देने पड़ते थे आज आपको 40 रूपये देने पड़ रहे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। भई, आपने लैटर दिया। मुझे समय तो दो सोचने का। आप समय भी नहीं देना चाह रहे। आपने जानबूझकर 5 मिनट पहले लेटर दिया है। आधे घंटे पहले दे सकते थे आप। परसों दे सकते थे। मैं नहीं बोलना चाह रहा, उस विषय पर और मुझे मजबूरन बाहर करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं।

श्री अनिल बाजपेयीः पहले 21 से 35 कि0मी0 का किराया 21 रूपये था आज 50 रूपये किराया है इसमें 22.50 रूपये देने पड़ रहे हैं। ये फर्क हैं। आज 21 से और 117 परसेंट किराया इन्क्रीज कर दिया गया है आज.

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। रोकने के लिए नहीं, मुझे बाहर करना पड़ेगा।

श्री अनिल बाजपेयीः 12 कि0मी0 से ऊपर 60 रूपये किराया दिल्ली के अन्दर किया गया। 114 परसेंट किराया बढ़ाया गया है। कलकत्ते के

अन्दर कोई रेट नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन आज गलत बात सुनने को तैयार नहीं हैं। सर, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बैठ जाएं। नहीं बैंठेंगे? नहीं बैठेंगे? रूलिंग दे चुका मैं। मैंने कहा आपका लैटर मुझे मिला है मैं देखूंगा उसको, बातचीत करूंगा और क्या रूलिंग दूं उस पर और रूलिंग क्या दूं? किस बात की रूलिंग दूं? मुझे मजबूरन मार्शल बुलाने पड़ेंगे। मैं सदन को अनुशासित ढंग से चलाना चाहता हूं। मार्शल्स सिरसा जी को लेकर जांए।

श्री अनिल बाजपेयीः आज पूरी दिल्ली के व्यापारी...

अध्यक्ष महोदयः कोई बात नहीं, मुझे चिंता नहीं, कोई बात नहीं।

... (व्यवधान)

श्री अनिल बाजपेयीः सर, मैं बताना चाहता हूं कि मैं गांधी नगर व्यापारिक क्षेत्र से आता हूं। आज पूरी दिल्ली का व्यापारी चाहे वो गांधी नगर का हो।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेण्ड, विजेन्द्र जी। बाजपेयी जी, अभी दो मिनट शांति से मेरी बात सुनेंगे। बैठाइए ओमप्रकाश जी को। बाजपेयी जी, बैठिए दो मिनट। अब उस बात में मेरे बीच में बोलना नहीं, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। देखिए दिक्कत आएगी, मैं नहीं बोलना चाह रहा। मैंने विपक्ष से प्रार्थना की कि आज आपने 5 मिनट पहले मुझे पत्र दिया। भई विजेन्द्र जी, नहीं, बात है, बात है ना, मैं बता

रहा हूं, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप बार–बार बीच में बोल रहे हैं, नहीं, बार–बार बीच में बोल रहे हैं। नहीं, मुझे पूरी बात करने दीजिए। हां, बैठिए आप।

मैं इस विषय पर ये कहना चाह रहा हूं कि विपक्ष को इतनी चिंता थी तो उसी वक्त इनको ये विषय उठाना चाहिए था वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद सदन में आए तो भी उस दिन इन्होंने कोई विषय नहीं रखा। सोमनाथ जी, दो मिनट रूक जाइए प्लीज। अगर नेता विपक्ष को इतनी चिंता थी, इन्होंने परसों मुझे ओमप्रकाश जी के विषय में एक पत्र दिया सीट चेंज करने के लिए। उस दिन भी आपने मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं लाई। इसका मतलब ये सोची समझी, बाद की चाल है। मैं बोलना नहीं चाहता था। सदन की कार्यवाही को रोकने के लिए आपने किया, बैठ जाइए आप। बिल्कुल ये आना चाहिए था। आप नेता विपक्ष हैं। आपको कोई बात लगी थी, आपको आना चाहिए था। आपको बात बतानी चाहिए थी। हां, बाजपेयी जी, शुरू करिए। आपकी ये सोची समझी बात है ये कहीं से आपको आदेश आया है। आप बोल रहे हैं, चलिए। हां, मैंने बोल दिया, आपने सुना ही नहीं। आप बैठ जाइए। अभी दिल्ली में पूरे भारत से पेट्रोल कम है पूरे भारत से कम है। भाजपा के स्टेटों में करवाइए। बैठ जाइए। बाजपेयी जी, चलिए, ठीक है। अब मैट्रो किराए पर डिस्कस हो रहा है, चलिए। आपको सदन नहीं चलने देना है। आपने निर्णय किया हुआ है। मैट्रो के किराए पर वृद्धि को रोकने पर आप परेशान हो रहे हैं। वो मैट्रो के किराए पे चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। मैं चर्चा करवा कर रहूंगा, चाहे रात के 10 बजें।

... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार शर्माः जनता की भलाई के लिए कोई चर्चा नहीं होने देना चाहते।

अध्यक्ष महोदयः अब बैठिए प्लीज। नितिन जी, आप प्लीज सीट। अब उनको छोड़िए आप। आप उनका मुकाबला करेंगे? आप उनका मुकाबला करेंगे? आप अपनी सीट पे जाइए, बैठिए। आप बाजपेयी जी, बात पूरी करिए।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः सर।

अध्यक्ष महोदयः विषय बदल गया अब उनका। उनका विषय बदल गया है। आप शुरू करिए।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज पूरा दिल्ली का व्यापारी वर्ग मैट्रो के बढ़ते हुए किराए से परेशान है। अगर वेलकम मैट्रो स्टेशन से उसको कनॉट प्लेस जाना हो, सेन्ट्रल सैक्रेटेरिएट जाना हो तो 40 रुपये किराया देना पड़ेगा अगर पांच लोग जाते हैं 200 रुपया किराया हो गया। तो सर, कैब करेगा व्यापारी। आज वेलकम मैट्रो स्टेशन, सीलम पुर आपका कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, सदर बाजार जितना भी एरिया है। सारे व्यापारी, सारे व्यपारी रो रहे हैं आज। सारा व्यापारी कह रहा है कि मैट्रो का किराया कम होना चाहिए। मै इस सदन के...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये तरीका ठीक नहीं है।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः मैं इस सदन से।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः दिल्ली की जनता आज मैट्रो क लिए परेशान है। आप दिल्ली को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। दिल्ली को तबाही की ओर ले जा रहे हैं आप। करिए। चलिए। बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः सर एक।

... (व्यवधान)

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः जितने आज हाउस में मैम्बर हैं हमारे। सर, जितने हाउस के मैम्बर हैं। मैं इनसे अपील करता हूं आप लोगों को, मैट्रो का किराया आपका बढ़ा देते हैं या कम करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदयः आपके वित्तमंत्री का किसी ने एक ने आदेश नहीं माना किसी एक स्टेट ने। आपके वित्तमंत्री का आपकी 18 स्टेटों में शासन है किसी एक स्टेट में आपके मुख्यमंत्री ने आदेश का पालन नहीं किया। आप यहां बोल रहे हैं जुर्माना! आपकी एक भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने पालन नहीं किया। आप बोल रहे हैं यहां। हां, करिये आप। फिर देखेंगे। करवाइए शुरू। आप चर्चा नहीं चाहते हैं आज। बैठिए आप।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदयः पहले चर्चा इसपे होने दीजिए, पहले चर्चा इसपे होने दीजिए, फिर बाद में बात करेंगे। हां बाजपेयी जी, शुरू करें आप।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जितने लोग यहां सदन में बैठे हुए हैं। जितने सदस्य हैं, जितने मीडिया के लोग हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग मैट्रो का किराया कम देखना चाहते हैं या बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं। कम देखना चाहते हैं तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं, ये बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं आप लोगों से सर।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः और सारे लोग जो यहां पे बैठे हुए हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने 1500 करोड़ रुपये दिल्ली के लोगों को दिया है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बाजपेयी जी, एक सैकेण्ड। अब दो मिनट बैठिए। भाई सोमनाथ जी, प्लीज। अब बीच में टोकना नहीं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। विजेन्द्र जी, इस चर्चा को हम सार्थक रूप से लें। लेकिन आपने जो बात उठाई है, आप सदन में मुझे लग रहा है कि आप वायदा करें सदन में कि मैट्रो का किराया हम नहीं बढ़ने देंगे। मैं सदन में वायदा करता हूं कि मैं वित्तमंत्री जी से स्वयं प्रार्थना करूंगा कि वैट की दर कम करें, आप करिए वायदा। करिए वायदा, हां वायदा करिए आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैट्रो पे तो आप चर्चा करवा रहे हो तो जब आप मेरे को...

अध्यक्ष महोदयः उसमें भी कर रहे हैं। मैं वायदा, सदन का अध्यक्ष वायदा कर रहा है। अब इसमें कुछ नहीं चलेगा। मैंने वित्तमंत्री से बात करी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मिनट। ठीक है मैं मेट्रो पे, मैं अपना बयान दूं?

अध्यक्ष महोदयः बैठिए प्लीज, बैठिए। बैठिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। मैं अब खड़ा हूं। नहीं, अब इसमें बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं बयान दूं अपना?

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, बैठिए, प्लीज। अब मैं खड़ा हूं, बैठिए प्लीज। मैंने वित्तमंत्री जी से बात नहीं की। लेकिन दिल्ली की जनता के हित में मैं वायदा कर रहा हूं। आप मैट्रो के किराए बढ़ाने से रोकिए। मैट्रो के किराए बढ़ने से रोकिए। मैं वित्तमंत्री जी से वैट कम करवाऊंगा, रोकिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं, मुझे मौका दो न। अपनी बात तो पूरी करने दो। मुझे अपनी बात तो। मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मेरी बात पूरी होने दो। मैं कह रहा हूं मुझे मेरी बात तो पूरी होने दो, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः मैं सोच रहा हूं कि बोलू नहीं। मैं अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हूं। आप मजबूर कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे मौका दीजिए। लेकिन वैट, वैट कम होना चाहिए, 5 परसेंट वैट कम होना, करो। आपने सात परसैंट बढ़ाया है, सात परसैंट। सात परसैंट वैट बढ़ाया है आपने, पिछले एक साल में। पहले...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अरे भाई, मैंने बोल तो दिया आपको। अब मैंने बोल दिया, आप बयान दीजिए न। विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी, आप बयान दीजिए, आप करावएंगे कम? आप बोलिए, बयान दीजिए। इसका दिखाने का क्या फायदा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, ये एक मिनट।

अध्यक्ष महोदयः मैंने क्लीयर एक लाइन में स्टेटमेंट दी है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिए, विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैंने जो ध्यानाकर्षण किया है, सरकार इसपे जवाब दे।

अध्यक्ष महोदयः एक सैकेण्ड बैठिए, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये सरकार कह दे, जो आप कह रहे हो। सरकार बोले।

अध्यक्ष महोदयः मैं अध्यक्ष हो के कह रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप स्पीकर हैं।

अध्यक्ष महोदयः क्यों?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये नहीं, सरकार बोले।

अध्यक्ष महोदयः इसका मतलब स्पीकर कुछ नहीं होता!

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जो उनको बोलना है, वो बोलें।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए आप, बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लेकिन आप, आप सरकार से कहलवाइए।

अध्यक्ष महोदयः मैंने बोल दिया भाई।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सर, से कहलवाइए आप।

अध्यक्ष महोदयः मैंने बोल दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये स्पीकर के कहने से नहीं बनेगी बात। ये सरकार की बात है।

अध्यक्ष महोदेयः विजेन्द्र जी, आप बच के जा रहे हैं। आप अपने आपको बचा रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप पार्टी मैन तो नहीं हैं अध्यक्ष जी?

अध्यक्ष महोदयः न बिल्कुल नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप पार्टी मत बनिए आप। आप सरकार से बयान करवाइए।

अध्यक्ष महोदयः आप हर तरीके से अपने...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप बयान करवाइए सरकार से। सरकार ये बयान बोल दे।

अध्यक्ष महोदयः भाई, एक गांव में कहावत है अद भी मेरी पट भी मेरी, पतनाला वहीं गिरेगा, वो इनका हालत है या तो आपका केन्द्रीय सरकार पे कोई.... आप केन्द्रीय सरकार से।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप बोलिए न।

अध्यक्ष महोदयः आपने मेरे से कहा, आप मेरे से मांग कर रहे हैं न, छोड़िए आप। बैठिए आप। मैं दिल्ली की जनता के हित की बात कर रहा हूं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, छोड़िए, छोड़ दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अरे! मैंने कहा मैं वित्तमंत्री से कम करवाऊंगा। मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है। मैं वित्तमंत्री से कम करवाऊंगा। आप करवाइए। क्या बात कर रहे हैं? छोड़िए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बाजपेयी जी, आपका हो गया पूरा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बाजपेयी जी पूरा करें, बाजपेयी जी पूरा करें। बोलने दीजिए। भाई माननीय सदस्य बैठेंगे। बैठिए, प्लीज। सभी माननीय सदस्य बैठें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए प्लीज।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः अध्यक्ष, महोदय, हमारे डिप्टी सीएम साहब यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा डीएमआरसी मुनाफा कमाने वाली कम्पनी नहीं है। सर, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने बोला है। सर, अध्यक्ष महोदय।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, बैठिए प्लीज। बैठिए, बैठिए। जरनैल जी, बैठिए। अरे बोलने दो यार! क्या दिक्कत हो रही है? बोलने दो, प्लीज। बैठिए, जरनैल जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, बैठ जाइए। चलिए।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः मेरा पूरा नहीं हुआ है अभी। अध्यक्ष महोदय, हमारे डिप्टी सीएम साहब यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि डीएमआरसी मुनाफा कमाने वाली कम्पनी नहीं है। इसके खातों की जांच होनी चाहिए, इसके जो भी अकाउंट हैं। इसके खातों की जांच होनी चाहिए। एक सचिव

कमेटी में सरकार का व्यक्ति मौजूद था। उसके बाद सरकार की बगैर राय लिए मैट्रो के दाम बढ़ा दिए गए। अरे! आप सुनते क्यों नहीं हैं? कमाल करते हैं आप!

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं विजेन्द्र जी, ऐसा नहीं चलेगा। अब बाजपेयी जी, बाजपेयी जी, आप बाजपेयी जी, इधर देखकर बात करिए। आप मुझसे बात करिए।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः देखिए साहब, हम बार बार कह रहे हैं कि आज कलकत्ता से, कलकत्ता भी एक महानगर है। कलकत्ते में किराया दिल्ली के किराए से बहुत कम है और आज हमारे मुख्यमंत्री जी तैयार हैं 1500 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं वो कह रहे हैं कि मैट्रो हमें दे दो। हम मैट्रो को ठीक कर देंगे। वो कह रहे हैं कि मैट्रो हमें दे दीजिए। लेकिन ये विपक्ष और भाजपा के लोग और इनके केन्द्रीय मंत्री, आपके केन्द्रीय मंत्री भाजपा के हरदीप पुरी जी ने कहा कि तीन हजार करोड़ रुपये आएगा। मैं एक बात सदन के सामने कहना चाहता हूं कि तीन हजार करोड़ रुपये की बात हरदीप पुरी जी ने कही। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल ही कह दिया कि हम 1500 करोड़ रुपये दिल्ली के लोगों के लिए देंगे। पर शर्त है आधे आप भी तो दीजिए। लेकिन ये बिल्कुल...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप क्या बार बार हो रहा है? आपकी क्यों, मैं स्टेटमैंट दे रहा हूं। अध्यक्ष के नाते से मैं स्टेटमैंट दे रहा हूं। आप कहिए न।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, आप सरकार हैं क्या?

अध्यक्ष महोदयः एक सैकेण्ड मैं ओम प्रकाश जी, दो मिनट चुप हो जाइए।

अध्यक्ष महोदयः हाँ, मैं सरकार हूं और बोलिए? मैं सरकार हूं। सरकार का एक हिस्सा हूं। अध्यक्ष हूं। छोड़िए, इस बात को।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः सर, आज दिल्ली का सारा व्यापारी..

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप छोड़िए। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती!

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बदतमीज कहीं का! चलिए। बाहर जाइए। जाइए बाहर। ओमप्रकाश को बाहर करिए। ओमप्रकाश को बाहर करिए सदन से। बाहर करिए, उसको तुरन्त। शर्म नहीं आती!

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः सर, सारा व्यापारी सड़क पर है। आज। आज दिल्ली का सारा व्यापारी...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बाजपेयी जी, एक मिनट सिर्फ। देखिए, विपक्ष की नीयत नहीं थी कि मेट्रो के किराये पर चर्चा करें और इसलिए उनका और कोई ध्येय नहीं था। वो चाहते थे कि हम छेड़ें और बाहर करें। मैंने बहुत सहन किया। हां, बाजपेयी जी आरम्भ करिए।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः सर, मैं गांधी नगर क्षेत्र से आता हूं और सबसे ज्यादा रोष अगर किसी वर्ग में है तो मीडियम क्लास के अलावा व्यापारी वर्ग के अन्दर है। आज शाहदरा मेट्रो स्टेशन से अगर कोई व्यक्ति दिल्ली सेक्रेट्रिएट जाता है, चांदनी चौक जाता है तो उसको 15 रूपये किराया देना पड़ता था आज जस्ट डबल, तीस रूपया किराया उसको देना पड़ रहा है आज। अब अगर चार लोग सर, अगर मेट्रो में किसी को सीलमपुर मेट्रो से वेलकम मेट्रो से अगर सेक्रेट्रिएट जाना होगा तो उसका किराया हो गया 200 रूपये। अगर कैब कर लेगा तो चार आदमी चले जाएंगे। 150 रूपये में कैब चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा गैप है। डेढ़ लाख यात्री, जब से मेट्रो किराया बढ़ाया गया है और जब से पुराना किराया भी बढ़ोत्तरी की गयी है, नई में। डेढ़ लाख यात्री दिल्ली के अन्दर कम हुए हैं सर। ये आज दिल्ली ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में हमारी सरकार कर रही है लेकिन आज जो कई रूट पर हमारी बसें नहीं है, फीडर बसेज नहीं हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाउस में ये पास करना चाहिए की मेट्रो का किराया तुरन्त वापस लिया जाए और चाहे हम लोगों को कोई बड़ा आन्दोलन केन्द्र सरकार के खिलाफ करना पड़े। ये मेरी आप लोगों से अपील है सर। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदयः सुश्री भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, जेब पर भारी मेट्रो की सवारी। दिल्ली में मेट्रो का सफर मंहगा हो गया है। डीएमआरसी की जो फेयर फिक्सेसन कमेटी है, उनकी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में परिवहन का कोई भी साधन हो, वो अपने आप में दिल्ली की लाईफ लाइन कहा जाता है और फेयर फिक्सेसन कमेटी यानि किराया निर्धारण कमेटी ने दो किलोमीटर तक के सफर पर 10 रूपये, दो से पांच किलोमीटर तक के

सफर पर 15 रूपये, पांच से बारह किलोमीटर के सफर पर 20 रूपये, पन्द्रह से इक्कीस किलोमीटर तक के सफर पर 30 रूपये, इक्कीस से बत्तीस किलोमीटर तक के सफर पर 40 रूपये और बत्तीस से आगे जितने भी किलोमीटर तय होंगे उस पर 50 रूपये का किराया बढ़ाकर के तय कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक तौर पर ये सफर बहुत खर्चीला हो गया। दिल्ली देश की राजधानी है, अध्यक्ष महोदय, और एक सर्वे के अनुसार ये पता चला कि दिल्ली के अन्दर जितने भी लोग मेट्रो से यात्रा करते हैं, उसमें से अधिकांश बच्चे कालेज के स्टूडेन्ट्स हैं। दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं में पढ़ने वाले स्टूडेन्ट्स हैं और वे लोग शामिल हैं, जो महीने में लगभग दस हजार रूपये से लेकर पच्चीस हजार रूपये तक कमाते हैं। पचास हजार की सेलरी कमाने वाले बहुत कम लोग मेट्रो से सफर करते हैं। कलकत्ता के अन्दर भी मेट्रो चल रही है। दिल्ली से बहुत कई सालों पहले से मेट्रो का सफर कर रहे हैं कलकत्ता के लोग। लेकिन अगर वहां के किराये की तुलना करें तो लगभग दिल्ली का मेट्रो का किराया आज की डेट में दुगुना हो गया है। अध्यक्ष महोदय, जब डीएमआरसी के अधिकारियों से बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर हमने किराया नहीं बढ़ाया तो मेट्रो को काफी घाटा सहना पड़ेगा और यदि मेट्रो की सेवाओं को हम ठीक रखना चाहते हैं तो किराया वृद्धि होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में लोग भरपूर तरीके से टैक्स देते हैं लेकिन बदले में मेट्रो यात्रियों को क्या मिला? मई में एक बार किराये को बढ़ाया गया। अक्तूबर में दुबारा से मेट्रो के किराये को बढ़ाया गया। दिल्ली की नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय डूबने के कगार पर है। लगातार मंहगाई बढ़ रही है। रसोई से लेकर के परिवहन व्यवस्था अपने आप में

पूरी तरह से उनकी जेब खाली होती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो लगता है कि दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपने आप में बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचा पाता। उसे महीने का खर्चा अपने परिवार का निकालना, अपने आप में एक बहुत ही कठिन काम है। अध्यक्ष महोदय, जब डीएमआरसी के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि जापान का लोहा मंहगा हो गया, बिजली की दरें जो हैं, वो बढ़ गयी हैं। स्टाफ की कॉस्ट हमें देनी पड़ती है। रिपेयर और मेन्टेनेन्स की कॉस्ट के कारण हमने इस किराये को बढ़ाया है। सौ रूपये में से चौरासी रूपये आपरेशन के ऊपर खर्च किया जाता है और साल में लगभग पांच सौ करोड़ रूपया इण्ट्रेस्ट के तौर पर भी हमें दूसरे सिटीज को देना पड़ता है, जापान को देना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, 2016 में फेयर फिक्सेसन कमेटी का गठन हुआ। उसकी स्थापना हुई। दिल्ली सरकार को उन्होंने कहा कि आप लिखित तौर के ऊपर हमें टिप्पणी दें कि मेट्रो के अन्दर किन–किन नियमों को लागू करना चाहिए। 30 जून, 2016 को दो पेज का पत्र दिल्ली सरकार की तरफ से लिखा गया, जिसके अन्दर स्पष्ट तौर के ऊपर दिल्ली सरकार ने बढ़े हुए किराये को लेकर के एतराज जताया। अध्यक्ष महोदय, अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी के किसी भी काम में कभी भी किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इस साल अगस्त के महीने में दिल्ली मेट्रो यात्रियों की संख्या में लगभग पांच प्रतिशत की कमी आयी जबकि 2015, अगस्त में 8 प्रतिशत यात्रियों की संख्या बढ़ी थी। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे सवाल हैं डीएमआरसी से। क्वेश्चन नम्बर 1– अगर डीएमआरसी का मानना था कि किराये को बढ़ाने की आवश्यकता है तो फेयर फिक्सेसन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में आठ महीने का समय क्यों लगा? दूसरा सवाल है– अध्यक्ष

महोदय, मेट्रो किराया वृद्धि होगी तो यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। इसकी चिन्ता केन्द्र सरकार ने क्यों नहीं की? इसकी चिन्ता डीएमआरसी ने क्यों नहीं की? क्वेश्चन नम्बर 3– अगर दिल्ली मेट्रो अपनी वित्तीय स्थितियों को लेकर के चिन्ता में था तो 2009 से लेकर के 2016 तक किराये में किसी प्रकार का संशोधन क्यों नहीं किया गया? अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नम्बर 4 है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार उसके मेम्बरान और एक ऐसी मेट्रो जिसके अन्दर केन्द्र सरकार का और दिल्ली सरकार का आधा–आधा अधिकार क्षेत्र है तो अगर दिल्ली सरकार की किसी राय को मानना ही नहीं तो फिर हमें इसमें शामिल क्यों किया गया?

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। फेयर फिक्सेसन कमेटी ने दो बार किराये की वृद्धि के बीच का अन्तर कम से कम एक साल का होना चाहिए। ये जब कमेटी ने खुद अपनी तरफ से इस विचार को बनाया। तो फिर इस विचार का उल्लंघन क्यों किया? एक तरफ मई में वो किराया बढ़ा रही है, दूसरी तरफ अक्तूबर वो किराया बढ़ा रही है और ये उसी कमेटी का बनाया हुआ नियम है। तो इसका मतलब स्वयं नियम बनाते हैं और स्वयं उसका उल्लंघन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक अन्तिम प्रश्न ये है कि आठ साल बाद में फेयर फिक्सेसन कमेटी को गठित करने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? और वो भी आठ साल बाद में! अध्यक्ष महोदय, राज्य में रहने वाली जो भी सरकारें हैं, उनका सीधा–सीधा दायित्व बनता है, अच्छी बिजली दें, अच्छा पानी दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और अच्छी परिवहन व्यवस्था दें। दिल्ली राज्य के अन्दर परिवहन व्यवस्था स्वाभाविक तौर पर दिल्ली की लाईफ लाईन कही जाती हैं। मैं जानती हूँ इस बात को कि राज्य सरकार, उसकी जिम्मेवारी तय है कि वो सस्ता, सरल और सुलभ उपलब्ध होने वाली परिवहन व्यवस्था दिल्ली के लिए रखे।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली मेट्रो के ऑपरेशन विभाग के कुछ अधिकारियों से हमारे विधायक स्वयं भी जाकर के मिले थे और मुझे लगता है कि यह 5 प्रतिशत की मेट्रो के अंदर यात्रियों की कमी, यह जो कमी आई है, यह इस बात को दर्शाती है कि बढ़ा हुआ किराया दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों की जेब के ऊपर भारी खर्च के रूप में पड़ा है और वो गरीबी और मंहगाई को सहने के बावजूद उन्हें लगा कि शायद मेट्रो को छोड़ कर के कोई और यातायात का साधन हमें अपनाना पड़ेगा और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, डीएमआरसी के संबंध में केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के पास बराबर–बराबर के अधिकार हैं। इसलिए अंत में, मैं केवल एक ही निवेदन आपसे करूँगी कि दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 की धारा–86 के अंतर्गत डीमआरसी को निर्देश दें कि वो अपने बढ़े हुए किराये को वापस लें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद दूंगी।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो इस ज्वलंत मुद्दे के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे तो यह भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए, कहीं पर भी किसी भी स्टेट के अंदर यदि कोई किराया बढ़ता है तो विपक्ष सबसे पहले हो–हल्ला करता है लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका से बिल्कुल नदारद रहता है, जनता के हितों के साथ वो खिलवाड़ करता है। अरे! जनता ने इस सरकार को चुन कर भेजा है और इसके अंदर दखलंदाजी सेंटर यदि इसी हिसाब से कर रहा है कि दिल्ली की जनता को वो एकदम से मारना चाह रहा है। जब दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को पानी देना है, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करनी है, लोगों की शिक्षा की चिंता करनी है तो मेट्रो के किराये की

चिंता भी दिल्ली सरकार को ही करनी है। किसी सेंटर की सरकार को नहीं करनी और मेरे साथी बहुत रोड़ा–रद्दा कर रहे थे, बहुत खप्प पा रहे थे। इनके लिए कहता हूँ, 'सोना होता है ना, सोने के कितने भी टुकड़े हो जाएं, वो कहते हैं लाख टुकड़े हो जाएं सोने के, पर उसकी कीमत कम नहीं होती। अरे! लाख भौंकते रहिये सियासतदान अरविंद केजरीवाल की चमक कम नहीं होती। अरे! जनता के हितों की बात करो तो अच्छा लगेगा विजेन्द्र जी। आप भी जनता के नुमाइंदे हैं। अपने कर्त्तव्यों के प्रति आप जागरूक हो जाओ, यह मेरा आपसे निवेदन है। आप देख रहे हैं आज 2 से 5 किलोमीटर के 9 मई, 2017 तक किराया क्या था 11 रुपये और 10 मई को वो किराया हो गया 15 रुपये और अक्टूबर, 2017 को वही किराया बढ़कर 20 रुपये। अरे! ऐसी क्या चीज हो गई जो इतना किराया बढ़ रहा है और कलकत्ता के अंदर देखो, जो हमारे यहां से पहले की मेट्रो चली हुई है, वहां पर किराया है तो सिर्फ 5 रुपये है। चार गुणा का फर्क, यह शर्म की बात है! दिल्ली की जनता से सिर्फ एक ही कसूर हुआ है कि उनका अश्वमेध रथ जो चलता हुआ आ रहा था, दिल्ली की जनता ने यहां पर रोक दिया। उनके अहंकार को यहां पर चकनाचूर कर दिया, यही कसूर है दिल्ली की जनता का और कोई कसूर नहीं है। यही किराया 5 से 12 किलोमीटर का जो 13 रुपये था 9 मई को और 10 मई को यही किराया 20 रुपये हो गया, 15 रुपये से 20 रुपये यह किराया और 10 अक्टूबर को यही किराया 30 रुपये, कितने बड़े शर्म की बात है। सीधा डबल! मैं पूछना चाहता हू आपके माध्यम से नेता, प्रतिपक्ष से, अरे! जनता की कितनी कमाई बढ़ा दी, कितनी तनख्वाहें बढ़ा दीं? कमाइयाँ तो घट गईं, पहले तो नोटबंदी लगी सभी के नोट, जितना भी थोड़ा बहुत कुछ रह गया था वो जीएसटी ले गई। आज तक लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रही, इनको भी खुद समझ नहीं आ रही, यह भी बात सही है। इनको तो सही

पूछो ना, सरकार ही चलाने की समझ नहीं आ रही, अब की बार 2019 में, अध्यक्ष जी, कई बार... महेन्द्र गोयल, कन्क्लूड करो। 12 से 21 किलोमीटर का किराया 9 मई, 2017 को 19 रुपये और 10 मई को किराया बढ़कर 30 रुपये और 10 अक्टूबर को वही किराया 40 रुपये 111 परसेंट बढ़ा, यह किराया। कितने बड़े शर्म की बात है! लोगों की तनख्वाह तो घट गई, लोग बेरोजगार हो गए सब, क्योंकि नोटबंदी के अंदर लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गईं और कहीं पर जब जीएसटी आई, उस टाइम तो सारा का सारा व्यापार ही चौपट हो गया। यह और कुछ नहीं है, सिर्फ दिल्ली की जनता के साथ उस हार का बदला लेने के लिए है और यही किराया देख लो 15 रुपये कोलकाता के अंदर है। कहां पर 40 रुपये दिल्ली के अंदर। अरे! कोलकाता इसी देश का हिस्सा है और वहां पर किराया यह 15 रुपये, कितना बड़ा फर्क नजर आ रहा है। 21 से 32 किलोमीटर किराया होता है 25 रुपये और 10 मई को वो 40 रुपये.

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, ऐसे तो नहीं। वो बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगी।

श्री महेन्द्र गोयलः आपके पास सब कुछ है ना, कलकत्ता के अंदर साढ़े 22 रुपये....

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं।

श्री महेन्द्र गोयल : चलो, एक काम करते हैं...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मेट्रो की लाइन ज्यादा बढ़ने से एक्सपेंडिचर का वेटेज जो है, पर पर्सन कम होता है। छोड़िये, आप बैठिये।

श्री महेन्द्र गोयलः नितिन भाई, ये बिल्कुल सही ट्रेक पर आ रहे हैं, एक मिनट, एक मिनट....

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, बैठिये। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ आप अपनी राह से मत भटकें, वो चर्चा नहीं चाहते, इसलिए बार–बार परेशान कर रहे हैं। आप थोड़ा बैठिये प्लीज। चलिये, कन्क्लूड करिये।

श्री महेन्द्र गोयलः कन्क्लूड तो आपको बताया, अध्यक्ष जी, मेरा तो वही जवाब है और 32 किलोमीटर या इससे ऊपर यह किराया 9 मई को 28 रुपये और 10 मई को सीधा 50 रुपये। ऐसा क्या हो गया उसके अंदर? क्या पानी की बोतल देने लगे हैं मेट्रो के अंदर या खाने का डिब्बा देने लग गए थे जो इतना किराया बढ़ा दिया? और 10 अक्टूबर को वही किराया 60 रुपये, छह महीने के अंदर। छह भी नहीं हुए, ये तो इससे भी कम हैं पाँच ही हुए। पाँच महीने के अंदर डबल से भी ज्यादा किराया, यह बड़े शर्म की बात है! मेरे साथियों से, नेता विपक्ष से एक ही पूछना चाहूँगा कि क्या इस किराया बढ़ाने के आप हक में है? आपके माध्यम से यह तो चाहूँगा, दिल्ली की जनता जवाब मांग रही है इस बात के लिए और मैं धन्यवादी हूँ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री का कि सूरी साहब ने कहा कि तीन हजार करोड़ यदि किराया नहीं बढ़ाना तो आप केन्द्र सरकार को तीन हजार करोड़ रुपये दे दो और तुरंत ही मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि दिल्ली की 50 परसेंट की हिस्सेदारी है तो 15 सौ करोड़ रुपये हम देते हैं और ये किराया बढ़ने नहीं देंगे। कितने उदार दिल हैं वो। देखिये, एक तरह से पानी के बिल

टोटल के टोटल माफ। बीस हजार लीटर तक कोई कितना भी पानी पी लो कितना पानी खर्च कर लो कोई भी बिल नहीं। हास्पिटलों के अंदर आप चले जाओ, दवाइयां सारी की सारी फ्री। महंगे से महंगे टेस्ट भी दिल्ली सरकार ने फ्री करे हुए हैं और यहां पर आपने 15 सौ करोड़ मांगे हैं, तो वो भी देने के लिए तैयार हैं। जनता का हक मत मारो। लोगों को मेट्रो के अंदर सफर करने दो। ये जनता का कसूर नहीं होता आपको कहीं न कहीं अहंकार आ गया था तभी आपका ये रथ रोका था इस जनता ने। इस जनता से प्यार करें। इनके हक के लिए आप भी बात करें और मैं आपके माध्यम से सीएम साहब तो यहां नहीं हैं, डिप्टी सीएम साहब हैं। यदि नेता प्रतिपक्ष जनता के हितों की बात को न उठाएं तो इस पद को खत्म करने का काम करें, ये भी काम कर दें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमें क्या है? सत्ता की भागीदारी के अंदर रहते हुए सत्ता की बात भी हमें करनी पड़ती है और नेता प्रतिपक्ष की भी बात हमें करनी पड़ती है, ये काम करना पड़ेगा। ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। ये जनता के हितों की बात करने के लिए विधानसभा का गठन होता है। उसके हितों के प्रति जागरूक रहें, जयहिन्द जयभारत।

अध्यक्ष महोदयः बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी।

श्री मनोज कुमारः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि दिल्ली की जनता का जो दर्द है जो उभरकर के सामने दिखाई दे रहा है, आज मेट्रो का किराया जो बढ़ा रहे हैं, उस पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

आज जिस प्रकार केन्द्र की सरकार बार बार जनता के साथ छल कर रही है, पहले ही देश की, दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने नोटबंदी करके पूरे देश में आर्थिक संकट जो इन्होंने खड़ा किया है, आज उसी तरफ

ये दिल्ली को मेट्रो का बढ़ा हुआ किराया देकर के और दुःखी करने का काम कर रही है केन्द्र सरकार। आज मेरे कई सारे साथियों ने इस पर चर्चा की और कहा भी है कि ये दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया जा रहा है, जो जनता को परेशान किया जा रहा है, वो उसका सिर्फ एक ही कारण है और वो ये कि दिल्ली की जनता ने इन्हें सिर्फ तीन सीटें दी। उसकी वजह से ये दिल्ली की पूरी जनता को परेशान करने पर लगे हुए हैं। किसी न किसी रूप से आगे बढ़ाने पर। हम कोई भी काम करने लगें, जनता के हित के लिए काम करें, उसको रोकने के लिए कोई न कोई अड़ंगा लगाते जा रहे हैं लगातार। हमारी सरकार ने, जैसे अभी गोयल साहब ने कहा कि सारे टेस्ट फ्री करके दिये। पहले भी सरकारें रही हैं। अस्पताल पहले भी वही थे। डॉक्टर भी वही थे और मरीज भी वही थे परन्तु पहले और आज में इतना जमीन आसमान का फर्क आया है सरकार की वजह से कि आज पूरे देश भर में ही नहीं, पूरी दुनियां में दिल्ली की सरकार की तारीफें की जा रही हैं। वो तभी हो पा रहा है कि जब दिल्ली की सरकार की नीयत है जनता के हित में काम करना। जो वादे करके हम आए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए हमें ये संघर्ष करना पड़ रहा है। बार बार, छह महीने के अंदर दो बार इन्होंने किराये बढ़ाये जबकि जैसा भावना जी ने बताया कि साल भर में एक बार कम से कम किराया बढ़ता है और इन्होंने छह महीने के अंदर कई गुना किराया बढ़ा दिया जिससे दिल्ली की जनता पर, उसकी जेब पर जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण आज दिल्ली कर रही है, उस पर इन्होंने वो अंकुश लगा दिया कि किसी भी तरह से मजदूर और गरीब हो जाए और नीचे दबे उस पर ये काम कर रहे हैं न कि जनता के हितों में कोई काम कर रही है केन्द्र सरकार। केन्द्र के मंत्री जी ने कहा कि जी, अगर किराया नहीं बढ़ा न, तो जो घाटा 3 हजार करोड़ का होने जा रहा है उसके लिए केजरीवाल

सरकार तीन हजार करोड़ रुपये हमें दे, हम किराया नहीं बढ़ाएंगे। ये केजरीवाल सरकार हमारे इस दिल्ली की अपनी सरकार है जिसने तुरंत ही ये जवाब दिया कि जी मैं 50 प्रतिशत हिस्सेदार हूं तो 15 सौ करोड़ देने के लिए तैयार हूं आप भी 15 सौ करोड़ आज ही माफ करें पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। हम किसी भी सूरत में दिल्ली की जनता पर कोई बोझ पड़ने नहीं देना चाहते हैं। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यहां सभी माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले 3 साल में हमने एक भी पैसा बिजली के किराये में बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। हमने दिल्ली की इस जनता को पानी मुफ्त करके दिया 20 हजार लीटर प्रतिमाह, उसके बावजूद भी दिल्ली जलबोर्ड फायदे में आ गया। अगर इनसे नहीं चलती है मेट्रो केन्द्र सरकार से, तो दिल्ली सरकार को ये मेट्रो दें, हम इसे घाटे में से निकालकर मुनाफे में लाकर के, काम करके दिखाएंगे। ये तभी संभव हो पा रहा है जब दिल्ली की सरकार लगातार काम कर रही है जनता के हितों में। किसी भी देश, किसी भी राज्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात ये कमाई के साधन नहीं होते। ये उस जनता को दी जाने वाली सुविधाएं होती हैं जो वो अपने पैसे से अपनी कमाई का टैक्स देते हैं। उस वजह से इनको वो सुविधाएं दी जाती हैं परन्तु इन लोगों ने सिर्फ इन सब चीजों को कमाई का धंधा बनाकर रखा हुआ है कि कैसे भी स्कूलों को प्राइवेट करो, उनसे पैसा लूटो। सरकारी अस्पताल खराब करो, प्राइवेट इनके मंत्री इनके विधायक खोलें ताकि ये फायदे में जाएं लेकिन दिल्ली की सरकार सिर्फ दिल्ली की जनता की सरकार है, उसके लिए हम प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगा रहे हैं सरकारी स्कूलों को अच्छा कर रहे हैं। हम प्राइवेट अस्पतालों पर अंकुश लगा रहे हैं क्योंकि हम दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को वर्डक्लास क्वालिटी का बनाने जा रहे हैं। वैसे ही यातायात को हम सबसे बेहतर बनाने की जो कवायद शुरू की हुई है, उसमें अगर ये योगदान

नहीं देते हैं तो ये हमें मेट्रो दें। हम इन्हें चलाकर के दिखाएंगे, इसे मुनाफे में लाकर के दिखाएंगे। मैं जिस विधानसभा से आता हूं, कोण्डली से, मैं कई बार सदन में सारी चीजें रख चुका हूं अपनी कोण्डली की। मैंने पिछली बार, मैं थोड़ा सा इससे हटकर बात कर रहा हूं मैं आपकी अनुमति चाहूंगा बस, एक मिनट इस पर लूंगा आपका कि कूड़े के ढ़ेर के बारे में बात की थी और मैंने इसी सदन में खड़े होकर 2015 में कहा था कि इसमें मीथेन की वजह से कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और वो हुआ, वहां दो बच्चों की जान गई। एमसीडी की तरफ से उनको एक पैसे का मुआवजा, उनको अभी तक नहीं मिला। उनके किसी परिवार को एक नौकरी नहीं दी गई। जब तीन बच्चे सीवर में गलती से ठेकेदार की गैस की वजह से मरे थे तो दिल्ली सरकार ने दस लाख रुपये का मुआवजा दिया था। उनके परिवार को सिविल डिफेंस में नौकरी दी। उस समय तो भाजपा ने खूब चिल्लाकर कहा कि हमारे बच्चे कब तक मरते रहेंगे? ये तो सर, कोई प्राकृतिक डिजास्टर नहीं था, ह्यूमैन डिजास्टर था एमसीडी का, जिसकी गलती से वो दोनों बच्चे मरे। आज इनके पास उस पर कोई जवाब नहीं है। मेरे यहां पर मेट्रो का यार्ड बना दिया कोण्डली के अंदर। पूरी मेट्रो आएगी, उसकी गंदगी वहां पर डाली जाएगी, धुलाई होगी परन्तु दिल्ली में कोण्डली को मेट्रो की लाइन नहीं दी गई, एक स्टेशन नहीं दिया गया। क्या कोण्डली सिर्फ कूड़े का ढ़ेर बनकर रहने के लिए तैयार है क्या? क्यों हमारे साथ हमेशा पक्षपात किया जाता रहा। पूर्व की सरकारें रहीं, किसी भी सरकार ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। पूर्व के विधायक जो डिप्टी स्पीकर रहे, जो वहां से सांसद रहे कांग्रेस के, उन्होंने लिखकर के डीएमआरसी को दिया कि कोण्डली में जरूरत नहीं है। आज भी वही व्यवस्थाएं वहां पर हो रही हैं। माननीय एलजी महोदय के आदेशानुसार कूड़े को बंद कर देना था परन्तु वो अभी भी बंद नहीं हुआ है। सर, मैं इस

सदन से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि मेरी कोण्डली में भी जो यार्ड बना है, कम से कम उसको एक मेट्रो स्टेशन दिया जाए ताकि कोण्डली की जनता भी दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार को खूब बधाई दे सके। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं स्पीकर साहब, कि आपने मुझे इस ज्वलंतशील मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया और मेरी पीड़ा को समझकर के मेरी कोण्डली को भी कुछ दीपावली का उपहार दिया जाए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

अध्यक्ष महोदयः ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

जब 2013 से पहले जब दिल्ली में सरकारें होती थी तो हर साल बिजली के दाम बढ़ जाया करते थे और ये सब कम्पनी वाले के साथ मिलकर सब अपना सब गेम खेलते थे और घाटा दिखा–दिखा कर, दिखा–दिखा कर बिजली का बिल बढ़ाते गए और दिल्ली का गरीब आदमी जो सब है, वो पिसता रहा, पिसता रहा। अब ये डीएमआरसी का नया घाटा आ गया है। 2013 में माननीय मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल बने। हमारी सरकार बनी। उसके बाद बिजली कम्पनी सब का जो घाटा था, वो उसके बाद घाटा ही नहीं होता है। उसके बाद पता नहीं कौन सा फार्मूला बदल गया, कौन सा फार्मूला पहले था, कौन सा फार्मूला अब है? जैसे ही सीएजी को जांच के लिए आदेश किये, उसके बाद घाटा ही नहीं होता है। तीन साल हो गया, उससे भी ज्यादा बिजली कम्पनी का घाटा भी बंद हो गया और बिजली का बिल बढ़ना भी बंद हो गया और 50 प्रतिशत का हम लोग सब्सिडी दिये। दिल्ली के लाखों लोग खुश हैं। हर किसी को फायदा मिल रहा है।

अब ये डीएमआरसी मैट्रो रेल, मैट्रो रेल क्या है? दिल्ली के लिए, लाईफ लाइन है, लाईफ लाइन! और 32 लाख लोग रोज मैट्रो में सफर करते हैं। ये कौन लोग है भई? गरीब स्टूडेंस। बिहार उत्तर प्रदेश से आते हैं पढने के लिए। सस्ती जगह पर कमरा लेते हैं पढ़ने के लिए लेकिन बड़े–बड़े कॉलेज में जा करके पढते हैं। क्यों मैरिटोरिएस स्टूडेंस, सब होता है। मैट्रो से जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दूसरा गरीब आदमी सब।

जैसा कि अभी बता रही थी भावना जी। दस हजार रूपये कमाने वाला आदमी से लेकर के 25 हजार रूपये कमाने वाला आदमी सब, सबसे ज्यादा मैट्रो का इस्तेमाल करता है। तीसरा लोअर मिडल क्लास और मिडल क्लास। हम लोगों ने, यहां की सरकार ने जब मैट्रो के बारे में सोचा था, तब प्लान किया था तो उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य ये था कि दिल्ली एक ओवर पोपूलेटिड जगह है। जिसके पोपूलेशन को अगर ठीक करना है, यहां पर यातायात जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, इसको बैलेंस बनाना है, ठीक करना है तो इसके लिए मैट्रो की जरूरत है। यानि की 32 लाख लोग जो मैट्रो में सफर करते हैं, ये वो बैलेंस है रोड ट्रांसपोर्ट का, मैट्रो ट्रांसपोर्ट का, रेल ट्रांसपोर्ट का। अगर इसका संतुलन बिगड़ा तो पूरी दिल्ली की व्यवस्था चरमरा सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक षडयंत्र है। डीएमआरसी एक्ट कहती है 30 हजार करोड़ का घाटा हो गया। जैसे पहले बिजली कम्पनी चिल्लाया करती थी, घाटा हो गया... घाटा हो गया... घाटा हो गया... अब ये डीएमआरसी कह रही है कि तीन हजार करोड़ का घाटा हो गया। कौन जांच किया इसका कि घाटा हुआ कि फायदा हुआ? डीएमआरसी अपने आप ही कहते हैं। कोई फेयर कमेटी है जिसका जिक्र अभी भावना जी कह रही थी। तो भैया ये घाटा हो गया तो कलकत्ता में क्यों कभी घाटा हो गया था। कलकत्ता वालों का तो आपने सौ प्रतिशत

सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया घाटा। तो दिल्ली के साथ क्या भेदभाव! कैसी नजर है जो कलकत्ता पर है और दिल्ली में बैठकर दिल्ली में नहीं है। यदि विजेन्द्र गुप्ता जी का इन्ट्रेस्ट है, इनको पता लग रहा था। सौ परसैंट घाटा कलकत्ता मैट्रो का, इन्होंने रिफंड किया है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने कहा, क्योंकि 32 लाख लोग जो मैट्रो में सफर करते हैं, वो 32 लाख परिवार के प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके लिए सोर्स आफॅ अर्निंग है। उनका वो घर चलाते हैं। लाखों लोगों को नुकसान हो रहा है। साठ रूपया कहीं किराया होता है क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का? और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जनरेट करके हम लोगों ने क्या किया? गाड़ियों की संख्या रोड से कम करने की कोशिश की, बैलेंस करने की कोशिश की और आप ने क्या किया? मई के अंदर किराया बढ़ा दिया। किराया बढ़ाते ही मैट्रो के अंदर लाखों लोग जो सफर करते थे, उन कम्यूटर की संख्या दो लाख लोगों की कम हो गई। अब आप जैसे ही किराया बढ़ाओगे, लाखों लोग और कम हो जाएंगे।

अरे भैया! आपका घाटा कम नहीं हो सकता है किराया बढ़ाने से। अगर किराया बढ़ाने से घाटा कम होता तो 28 परसैंट जीएसटी लगाने के बाद आपका रेवेन्यू बढ़ जाता। तो भैया, ये कौन सा फार्मूला है जो 60 रूपया आप किराया कम करेंगे तो वो तीन चार लाख आदमी जो मैट्रो यूज करना बंद करेगा, वो कहां जाएगा? वो चलाएगा मोटर साईकिल। उससे क्या होगा? पोलूशन। दिल्ली के अंदर वैसे भी ठंड के दिनों में गैस चैम्बर बन जाता है। सरकारें चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। आदमी सब बीमार पड़ रहा है। इसका व्यापक आपको सोचना पड़ेगा कि इम्पैक्ट क्या होगा। ये सवाल सिर्फ फेयर के बढने का नहीं है। सारा हैल्थ व्यवस्था, पर्यावरण सब कुछ चौपट हो जाएगा क्योंकि मोटर साईकिल की संख्या बढ़ेगी, कारों

की संख्या बढ़ेगी और मैट्रो में जो लोग सफर करते थे, उसका पूरा लोड बसों पर पड़ेगा। जिसके लिए पूरा का पूरा ये बैलेंस सिस्टम है, बसों का, गाडियों का, मैट्रो का, ये सब कुछ आपस में चरमरा जाएगा। अभी अपने को समझने की जरूरत है कि ये जो ट्रासंपोर्ट सिस्टम है हमारा। बत्तीस किलोमीटर के लिए कहते 60 रूपये लेंगें और अध्यक्ष महोदय, ये चार्ट बनाकर आएं हैं हम लोग। एक सौ सत्रह परसैंट का हाईक! एक सौ सत्रह परसैंट फेयर हाईक! सेलेरी तो दस परसैंट भी हाईक नहीं मिलता है। वो भी नोट बंदी, जीएसटी आदमी सब करा रहा है डर से। जीएसटी और नोट बंदी का । एक सौ सत्रह परसैंट का फेयर हाईक! हिन्दुस्तान तो छोड़ो, हम तो खोजने का कोशिश किया गूगल में, विक्की पीडिया मे। दुनिया में कहीं नहीं मिला। आज तक कभी नहीं हुआ इतिहास में। तो दिल्ली के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? यहां पर दिल्ली मैट्रो के अंदर दिल्ली सरकार के साथ–साथ सैन्ट्रर भी स्टेक होल्डर है। you are the fifty percent of the state holder in DMRC. तो माननीय मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भैया, लोगों के ऊपर इस चीज का भार न पड़े। वैसे भी आप सब इससे परेशान हैं जीएसटी नोटबंदी से। तो ये तीन हजार करोड़ का जो सवाल है ये 1500 करोड़ रूपये हम दे देते हैं। अगर सैन्ट्रल 50 प्रतिशत देने के लिए तैयार होता है तो। लेकिन ये लोग अभी तक कोई तैयार ही नहीं है। कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। लेकिन एक चीज कहना चाहते है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को, उनके प्रतिनिधियों को विजेन्द्र गुप्ता जी के माध्यम से सब लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर दिल्ली की मैट्रो का किराया आप लोगों ने बढ़ाया तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। चाहे किसी का घेराव करना पड़े। किसी का पुतला फूकंना पड़े। लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि 32 लाख लोग, वो लोग हैं जो कि अपने घर के लिए

ब्रेड और बटर लाते हैं। उसमें गरीब लोग है जो स्टूडेंस हैं जो डेली बेसिज पर किसी भी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर आसानी से किराये पर जगह मिल जाए, सस्ता मिल जाए और स्टूडेंस को वो है, तो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। उनका भविष्य का सवाल है। वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 32 किलोमीटर का किराया 60 रूपया एक तरफ से। तो ये बहुत बडा सवाल है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि कुछ भी हो जाए, ये सदन एक मत हो करके आज इस पर प्रस्ताव पारित करे कि दिल्ली मैट्रो का किराया नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढना चाहिए। अगर आप कलकत्ता मैट्रो का 100 परसैंट रिफंड कर सकते हो तो यहां पर 50 प्रतिशत रिफंड करें ताकि यहां पर पर भी जिस तरीके से जो बैलेंस सिस्टम की मैं बात कर रहा था वो, किसी भी तरह से ना चरमराए और इसकी सीएजी से जांच भी होनी चाहिए कि सही मायने में इनको तीन हजार करोड़ का घाटा हो रहा है या जैसे दिल्ली के अंदर बिजली का घोटाला हुआ था। जैसे दिल्ली के अंदर बिजली कम्पनियों का घाटा हो रहा था। वही फार्मूला कहीं डीएमआरसी का भी तो घोटाला नहीं हो रहा है? बहुत–बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़लाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, इस दिल्ली के अंदर दो सरकारें चल रही हैं। एक तो दिल्ली सरकार और दूसरी केन्द्र सरकार। दिल्ली सरकार आम आदमी की सरकार जो आम आदमी के हितों के बारे में सोचती है। आम जनता से जुड़ी हुई बातों पर विचार करती है और दूसरी ओर केन्द्र सरकार जो कि बिल्कुल कोरे जुमले झूठे बाज, धोखे बाज लोगों

की सरकार है और यहीं पर एक दिखता है कि जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार चुनकर आई, बिजली के दाम आधे हुए, पानी माफ हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में प्राईवेट स्कूलों की फीस बढोतरी पर जो हर साल बेलगाम बढ़ोत्तरी होती थी, उस पर लगाम लगी। मिनिमम वेजिज बढाई गई मजदूरों की। स्वास्थ्य सेवाओं पर कम से कम पैसा खर्च हो, इसकी योजना दिल्ली सरकार की ओर से बनाई गई। दूसरी तरफ केन्द्र की जुमले बाज सरकार के आने के तुरन्त बाद पैट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी होने लगी। रेल के किराये में लगातार बढ़ात्तरी होने लगी। जीएसटी जैसी एक ऐसी योजना लाई गई जिससे आम साधारण लोगों के साथ–साथ जो एक व्यापारी वर्ग था, जो कभी मंहगाई को उसने महसूस नहीं करा। कभी उसके पास पैसे की कमी नहीं हुई। आज वो व्यापारी भी रो रहा है। नोट बंदी से लाखों लाख युवा बेरोजगार हो गए और अब केन्द्र सरकार की ओर से मैट्रो के किराये में बढ़ोत्तरी! अध्यक्ष जी, ये मैट्रो का किराया इसलिये नहीं बढाया जा रहा कि मैट्रो को घाटा हो रहा है, मैट्रो का किराया बकायदा एक साजिश के तहत बढाया जा रहा है ताकि दिल्ली की लोकप्रिय सरकार को बदनाम किया जा सके। दिल्ली की लोकप्रिय सरकार के ऊपर लांछन लगाया जा सके। अध्यक्ष जी, दिल्ली की जो मैट्रो है, मुझसे पूर्व तमाम वक्ताओं ने आपके बीच में एक कोलकत्ता की मैट्रो और दिल्ली की मैट्रो का किराये में जो डिफरेंस है वो भी बताया ये भी लगातार सारे साथियों ने बताया कि दिल्ली मैट्रो की लाईफ लाईन है और इस दिल्ली की लाईफ लाईन से लगभग तीस से बत्तीस लाख पैसेंजर लोग अपने जो हैं, अपनी अपनी चाहे वो स्कूल है, कालेज है, कार्य क्षेत्र है, वहां पर पहुंचते हैं ट्रैवल करते हैं। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही छोटी सोच और इसे कहें तो ये बहुत ही संकुचित मानसिकता का प्रमाण है कि एक और जहां पर कोलकत्ता में 100 परनसैंट मैट्रो को घाटा होता है तो केन्द्र सरकार जो अब कोलकत्ता सारे धन संपत्ति सारी

पॉवर से लैस होकर पूर्ण राज्य है लेकिन उस पूर्ण राज्य को भी सहायता देते हुए हमारी केन्द्र सरकार 100 परसैंट उनका जो है, घाटा पूरा करती है और दिल्ली स्वयं चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, पता नहीं कौन कौन से कोर्ट में केसिस भी डाले हुए हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां के मंत्रियों को पूरी पॉवर नहीं है, यहां का शासक, बिना चुने हुए एक एलजी है लेकिन वहां पर जब घाटे की बात आती है तो इनके केन्द्रीय मंत्री कहते हैं कि अगर मैट्रो के किराये को बढ़ने से रोकना है, तो दिल्ली की सरकार को दिल्ली के मुख्यमंत्री को तीन हजार करोड़ रूपये केन्द्र सरकार को देने होंगे।

अध्यक्ष जी, ये बहुत अटपटी सी बात है एक पूर्ण राज्य को सौ फीसदी घाटे से उबारने की बात हमारी केन्द्र सरकार करती है और कर दिखाया। दूसरी ओर आधी अधूरी शक्ति पर चलने वाला दिल्ली राज्य, उसको ये कहते हैं कि अगर आपको अपने राज्य में मैट्रो के किराये में बढ़ोत्तरी पर रोक लगानी है तो आपको तीन हजार करोड़ रूपये केन्द्र की सरकार को देना है। अध्यक्ष जी, मुझे बहुत अजीब लगता है लेकिन ये कहीं न कहीं सत्य है कि जिस पार्टी का अध्यक्ष तड़ीपार हो, वो पार्टी फिरोती ही मांगेगी और कुछ नहीं करेंगे और इन्होंने फिरोती के रूप में दिल्ली सरकार से तीन हजार करोड़ रूपये मांगे हैं।

अध्यक्ष जी, जब मैट्रो के अंदर डीएमआरसी के अंदर दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार की 50–50 फीसदी भागीदारी है तो ऐसी कौन सी आफत आ गई, ऐसा कौन सा कारण आ गया कि बोर्ड की मीटिंग में दिल्ली सरकार के नुमांइदों की एक नहीं सुनी जाती! और हम चाहते हैं आप मैट्रो का किराया वापिस ले लें बढ़ा हुआ, क्यों गलत बोल दिया, गलत बोल दिया ... (व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़लाः गलत तो नहीं बोला।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, क्या गलत बोला इसमें ?

... (व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़लाः किसको बोला नाम तो बताओ। किसको बोला, उसका नाम तो बता दो?

... (व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़लाः किसको बोला मैंने? किसको बोला मैंने तड़ीपार, नाम तो बता दो?

अध्यक्ष महोदयः मैं सुन रहा हूं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः उसमें असंसदीय शब्द नहीं है।

... (व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़लाः आप बैठ जाओ। हम रिकार्ड से वापिस ले लेंगे, आप मैट्रो का किराया बढ़ा हुआ वापिस ले लो। पता है आपको, तड़ीपार कौन है? तो नाम ले के बता दो एक बार सबको। आप बताओ, कौन है?

... (व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़लाः भई गुजरात की कोर्ट ने तो बता दिया। गुजरात की कोर्ट ने तो घोषित करा था तड़ीपार। भईया, गुजरात दंगों के बाद ही घोषित हुए थे तड़ीपार वो।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप!

... (व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़लाः आप बैठो, आपको काम धाम कुछ करना नहीं है, शोर मचाना है। मेरे सामने मत मचाया करो, बस। कोई भी बोले, मेरे सामने मत बोला करो, जब मैं बोल रही हूं तो। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदयः चलिये, चलिये।

... (व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, सिर्फ मेरा आपसे विनम्र निवेदन है और ये कुछ सवाल हैं मेरे मन में अगर केन्द्र और दिल्ली सरकार डीएमआरसी के अंदर मैट्रो के अंदर 50–50 फीसदी की भागीदारी रखती है तो जब बोर्ड की मीटिंग हो रही थी और दिल्ली सरकार के नुमांइदों ने लगातार इस बात का विरोध करा कि जो ये इस तरह से बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे जमीन की जानकारी लिये बिना जो इस तरह से सौ फीसदी से भी ज्यादा किराया बढाया जा रह है मैट्रो का, ये गलत है, ये नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार के नुमाइंदों की तरफ, उनके तर्कों की तरफ, उनके विचारों की तरफ, उनके सुझावों की तरफ बोर्ड ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया फिर किस बात की पचास परसैंट की भागीदारी ये लोग कहते हैं?

अध्यक्ष जी, जब बीजेपी की सरकार केन्द्र में अपना चुनाव प्रचार कर रही थी तो 2014 में इन लोगों ने नारा दिया था, 'बहुत हुई मंहगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार' और लगभग तीन साल बाद 2017 में दिल्ली

ही नहीं पूरे देश की जनता कहती है, 'बहुत हुई मंहगाई की मार, अब बस करो मोदी सरकार।' कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी पैट्रोल के दाम बढ़ा देना, बेचारी गरीब महिलायें, विधवा महिलायें, हम सब विधायक आये दिन इस समस्या से रूबरू होते हैं। उनकी जो पेंशन आती थी अध्यक्ष जी, अब वो पेन्शन इसलिये नहीं दे रहे हैं या इसलिये पेंशन नही आ रही क्योंकि जो मिनिमम बैलेंस एकाउंट में होना चाहिए था, वो केन्द्र सरकार ने बढ़ा कर पांच हजार कर दिया। ये कितनी अमानवीय सरकार है! जनता की और गरीबों की इन्हें बिल्कुल चिन्ता नहीं है लेकिन अडानी और अंबानी की इन्हें भरपूर चिंता है और उसी के कदम में ये बढ़ोत्तरी करते हुए मैट्रो के किराये को सौ फीसदी से भी ज्यादा बढ़ाने पर तत्पर तैयार हैं।

अध्यक्ष जी, ये समझ नही आता कि जो किराया निर्धारण समिति थी, उन्होंने वर्ष 2016–17 में कमेटी जब बनाई तो दिल्ली सरकार से उन्होंने लिखित में एक टिप्पणी मांगी थी कि दिल्ली गवर्नमेंट बताये की वो मैट्रो में किराया बढ़ाने के पक्ष में है या नहीं और दिल्ली सरकार ने अप्रैल में ही पत्र लिखकर अप्रैल के पत्र का 30 जून को जवाब देते हुए साफ तौर पर ये कहा था कि दिल्ली सरकार बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है और दिल्ली मैट्रो का किराया नहीं बढाना चाहिए लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ 8 मई को डीएमआरसी की बोर्ड में किराया निर्धारण समिति की सिफारिश के बारे में सूचित करा गया और अचानक से बताया जाता है कि मई, 2017 में बढात्तरी कर दी गई है।

अध्यक्ष जी, डीएमआरसी ने मैट्रो एक्ट की धारा 337 का उल्लंघन किया है और ये ये एक्ट कहता है अध्यक्ष जी, कि किराया निर्धारण समिति की सिफारिशें डीएमआरसी के लिये कम्पलसरी हैं। अगर किराया निर्धारण समिति

जो दिल्ली सरकार के जिसमें नुमाइंदे हैं, अगर वो किसी चीज पर ऑबजेक्शन करती है, अगर वो मना करती है तो डीएमआरसी बाध्य है, मजबूर है, उसके उस सुझाव को मानने के लिए, उसके उस विरोध को मानने के लिए। लेकिन किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों का, उनके तर्क का, उनके सुझावों का खुले आम कानूनी रूप से बहिष्कार करते हुए मई में तो इन्होंनें किराया बढाया ही, किराया निर्धारण समिति ये भी कहती है कि एक साल के अंदर एक बार ही किराया बढ़ाया जायेगा और सात परसैंट से ऊपर किराया नहीं बढा सकती डीएमआरसी लेकिन बोर्ड में पता नहीं क्या साठ गांठ है, पता नहीं क्यों ये जुमले बाज लोग अपने आकाओं को इतना फायदा पहुंचाने के लिए जनता को अपने पैरों तले अपनी नीतियों के नीचे इस तरह से कुचलने को मजबूर हो रहे हैं कि जनता त्राहि त्राहि कर रही है और इनकी और से मंहगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जब आप लोगों ने मई, 2017 के अंदर पहली किराये में वृद्धि कर दी थी, पहली बार किराया बढा दिया था तो अध्यक्ष जी, ये समझ से परे है कि ऐसी कौन सी आफत आ गई है, ऐसी कौन सी समस्या आ गई है, ऐसी कौन सी मजबूरी डीएमआरसी पर आ पड़ी है कि इन्हें अक्टूबर में लगभग चार से पांच छह महीने के बाद इन्हें पुनः जो है, किराया बढ़ाने की समस्या जो है, इनके गले नहीं उतर रही और इन्हें आफत में डाला हुआ है कि अक्टूबर में दोबारा से किराया बढ़ायेंगे।

अध्यक्ष जी, बहुत सारे स्लैब्स में जैसा हमने बताया और मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया, सौ प्रतिशत से भी अधिक जो है, किराये को बढाया जा रहा है। जो बहुत ही नुकसान दायक भी होगा और बहुत ही जनता की कमरतोड़ जो है, रेट होंगे लेकिन अध्यक्ष जी, जब हमारी किराया निर्धारण समिति ने ये साफ कर दिया था कि ये जो नियम हैं, वो 2019 में लागू

होगा। साठ परसैंट से अगर हमें ज्यादा किराया बढाना होगा लेकिन ऐसी कौन सी आफत आ गई कि दो साल पहले ही वर्तमान वर्ष 2017 में किराये को इस तरह से बढाया जा रहा है, बिना सोचे समझे। अध्यक्ष जी, ये बिल्कुल सही कहावत है कि जो लोग एसी में बैठकर सरकारें चलाते हैं, उन्हें आम गरीब लोगों की बिल्कुल चिन्ता नहीं है। मुझसे पूर्व जिस तरह से वक्ताओं ने बताया की मैट्रो में चलने वाला छात्र, मजदूर, महिला ये लोग, वो लोग हैं जो दस से बारह हजार रूपये महीने के कमाते हैं और ऐसे में अगर इनके मेट्रो के फेयर में लगभग सौ फीसदी से भी ज्यादा बढ़ोत्तरी होगी, तो ये सारी की सारी जनता जो है, सड़कों पर उतरेगी। सड़कों पर जाम लगेंगे, बसों में बढ़ोत्तरी होगी और न जाने क्या क्या समस्याएं आयेंगी!

अध्यक्ष जी, बस दो बातें कहकर अपनी मैं बात खत्म करूंगी कि किराया निर्धारण समिति ने डीएमआरी को सुझाव दिया था कि हांगकांग मेट्रो की तर्ज पर यहां पर भी उत्पादकता को बढ़ाया जाये, ये कदम डीएमआरसी की वित्तीय स्थिति को मजबूत तो करेगा ही, साथ में किराये की न्यूनतम वृद्धि को भी दिखायेगा। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी संस्था अपनी क्षमता को विकसित एवं कोष को कम करे, इस तरह का कोई भी कदम अगर डीएमआरसी की तरफ से उठाया जाता है तो ये हमें पूर्ण विश्वास है और हम लोगों ने दिल्ली में भी करके दिखाया है, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे हमारा बिजली विभाग हो, अगर हम टैक्सेज कम करेंगे, अगर हम किराया कम करेंगे, दरें कम करेंगे तो हमें मुनाफा ज्यादा होगा। बस अध्यक्ष जी, यही कहना चाहती हूं कि ये दिल्ली का पूरा सदन, दिल्ली विधान सभा में चुने हुए नुमाइंदे, हम उन बत्तीस लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, दिल्ली के हरेक नागरिक की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम सब लोग एक ही स्वर में उन लोगों का जो मैसेज है, उन लोगों का जो संदेश है, आपके

माध्यम से उपराज्यपाल को, नेता विपक्ष को और जितने भी हमारे केन्द्र में बैठे हुए लोग हैं, केन्द्र की सरकार है, सबको यही कहना चाहते हैं कि हम लोग मेट्रो का किराया नहीं बढ़ने देंगे। अगर फिर भी इतने विरोध के बाद भी लाख आंकड़े पेश करने के बाद भी अगर केन्द्र सरकार मेट्रो का किराया बढ़ाती हैं तो हमें, हम आंदोलन से निकली हुइ पार्टी हैं, हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं आंदोलन करेंगे और इस किराये को वापस कराकर ही छोड़ेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द जय भारत।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी। भई एक लूंगा, दोनों बात।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक चर्चा करवा रहे हो आप?

अध्यक्ष महोदयः अब बड़ा कठिन काम है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे तो आप, मुझे तो आपको बुलवाना ही है, आप मेम्बर...

अध्यक्ष महोदयः चलिये बैठिये, मैं बहस नहीं। बहस नहीं करना, जगदीश जी। बोलिये। मुझे उम्मीद है, जगदीश जी बढ़िया बोलेंगे।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं दो तीन बात कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदयः एक तो लेट आपने बहुत दिया पर्चा विजेन्द्र जी, बहुत लेट दिया। मैं तो सोच रहा था कि चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं तो पर्चा भरके यहीं रखा रह गया।

अध्यक्ष महोदयः ये तो आप देखिये, रखा रह गया।

श्री जगदीश प्रधानः कई माननीय सदस्यों ने पानी के ऊपर भी चर्चा की कि पानी के रेट नहीं बढ़े, बिजली के रेट नहीं बढ़े, पानी फ्री और बिजली हाफ! मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब कोई आदमी मकान बनाता है, एक कमरा या कमरे में एक खिड़की भी लगा रहा है तो बिजली अधिकारी कई बार मिसयूज लगाते हैं और...

... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधानः मैडम, ये पास कहीं कहीं है कि बिजली के रेट नहीं बढ़े। उसके ऊपर मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः पर जगदीश जी, मिसयूज तो पहले भी लगता था।

श्री जगदीश प्रधानः आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं कि किस तरह के काम...

अध्यक्ष महोदयः ये विषय नहीं है।

श्री जगदीश प्रधानः दिल्ली की जनता पर किस तरह के जुल्म हो रहे हैं। एक खिड़की अगर कोई लगाता है तो उस पर बीस, तीस, चालीस चालीस हजार का मिसयूज लगाया जाता है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जगदीश जी, एक सेकेंड। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अगर मकान बना रहा हूं तो कमर्शियल कनेक्शन लेना मेरे लिए कंपलसरी है, आप कमर्शियल ले लें।

श्री जगदीश प्रधानः सर, एक खिड़की बदलनी हो, तो भी कमर्शियल मीटर लिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदयः मैं कहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है?

श्री जगदीश प्रधानः सफेदी करी जायेगी, तब भी कमर्शियल मीटर लिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदयः नहीं ऐसा नहीं है। चलिये, आप बोलिये आप जो..

श्री जगदीश प्रधानः तीन चार आदमी...

अध्यक्ष महोदयः नहीं, जो आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिये, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री नितिन त्यागीः मेट्रो पे है ये।

श्री जगदीश प्रधानः सर, परिवहन समस्या पर तो बोल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदयः हां, बोलिये।

श्री जगदीश प्रधानः सर, मैं वही बोलना चाह रहा हूं, आज दिल्ली में, मैं कह रहा हूं कि किराया बढ़ने की बात कही गयी, जब डीएमआरसी की मीटिंग हुई, तो आपके सरकार के नुमाइंदे वहां थे, उनको वहां विरोध करना चाहिए था।

सुश्री राखी बिड़लाः किया था।

श्री जगदीश प्रधानः नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदयः चलिये ठीक है, बोलिये।

श्री जगदीश प्रधानः दूसरा, दिल्ली में जो जाम की समस्या है, चार साल के अंदर...

सुश्री राखी बिड़लाः अभी मेट्रो का किराया...

श्री जगदीश प्रधानः मैडम, जब आप बोल रही थी, चार चुप होते रहे। मैडम सुनिये आप।

अध्यक्ष महोदयः जगदीश जी, को बोल लेने दो।

श्री जगदीश प्रधानः मैं जो मेट्रो की बात है, मेट्रो की जहां दिल्ली के लोगों की लाइफ लाइन बन चुकी है और बसों का जो हाल बता रहा हूं आपको, मैं वजीराबाद रोड की बात कर रहा हूं, शास्त्री पार्क जाम की बात कर रहा हूं। जहां दो दो घंटे बस डीजल और मंहगी गैस फुकती रहती है और वहां निकल रहे हैं कूड़ा। चार साल के अंदर यदि दिल्ली में कोई फ्लाइओवर बनता तो मैं समझता हूं कि आज जो दिल्ली में दो दो घंटे जाम में लोग फंसे रहते हैं, वह नहीं फंसते और किराये बढ़ाने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती और अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा नहीं, आप कहने दे रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि मेट्रो का एक आज दिल्ली के लाइफ लाइन है और उसका किराया कम से कम होना चाहिए, मैं इतना ही आप से कहूंगा।

अध्यक्ष महोदयः किराया कम से कम होना चाहिए। विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, तथ्यों पर आधारित अगर चर्चा हो, तो वो ज्यादा बेहत्तर है और मैं देख रहा हूं कि तथ्यों पर चर्चा नहीं हो रही, यहां पर लच्छेदार भाषण हो रहे हैं। मैं आपको कुछ स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। ये मई 2016 में फेयर फिक्सेशन कमेटी कंस्टीट्यूट हुई, तीन महीने में उसने अपनी रिपोर्ट दी। मई 2016 में जो फेयर फिक्सेशन कमेटी गठित हुई, जो ये मेरे पास एक्ट है, यहां पर और इस एक्ट के अनुसार, ये एक्ट है डीएमआरसी का, इसके अनुसार एक चैयरमेन होंगे जो जस्टिस

एम.एल. मेहता बने और एक दिल्ली के नॉमिनी होंगे, दिल्ली गवर्नमैंट जिनको भेजेगी, वो फेयर फिक्सेशन कमेटी में होंगे और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी होंगे। इसको क्योंकि दिल्ली गवर्नमैंट और सेंट्रल गवर्नमैंट फिफ्टी–फिफ्टी परसैंट का इसमें शेयर है और ये ऑटोनोमस बॉडी है। ये किसी भी सरकार के, केन्द्र सरकार के तत्वावधान में नहीं है, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। रूल 37 जो डीएमआरसी एक्ट का कहता है, वो कहता है कि the recommendation made by the fare fixation committee shall be binding on the metro railway administration यानि कि ये जो स्टेच्युटरी बॉडी है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं, जो जिसके पास कंस्टीट्यूशनल राइट्स हैं। फेयर फिक्सेशन कमेटी का काम है, सारी चीजों का जायजा लेकर फेयर फिक्सेशन करना होगा और इससे भी बड़ी बात इसमें ये है कि जो बोर्ड है मेट्रो का, जिसमें पांच नॉमिनी हैं आपके, सरकार के, उसमें आपने ही अप्वाइंट किया है चैयरमेन को, जो डीएमआरसी के चैयरमेन हैं, उनकी अप्वाइंटमेंट दिल्ली सरकार करती है, वो आपके अप्वाइंटी हैं। फिर चीफ सेक्रेटरी आपने वो नोमिनेट किये, फिर आपने फाइनेंस सेक्रेटरी अपने नोमिन हो गये यानि की पांच लोग आपने नोमिनेट किये बोर्ड में और जो बोर्ड का कहना है, वो ये है कि ये जो बोर्ड में जब आयेगा, तो बोर्ड को कोई राइट्स नहीं है इसमें इंटरवीन करने का इस पर अपनी राय रखने का, ये एक तरह का फॉर इंफार्मेशन ही समझिए आप कि बोर्ड के सामने फेयर फिक्सेशन कमेटी का डिसीजन आ गया और वो इंप्लीमेंट होना है। उसमें कोई सरकार इंटरवीन नहीं कर सकती। एक तो ये भ्रम न फैलाया जाये कि जो मेट्रो है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। 15 साल से ये मॉडल बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, इसको हमें देखना पड़ेगा। हम एक चलते हुए सक्सेसफुल मॉडल को, जो कि दिल्ली की लाइफ लाइन बन गयी है और ये ऑटोनोमस स्टेट्स जो है, इसके कारण आज वर्ल्ड क्लास मेट्रो हमारे पास है, हमको गर्व होता है जब हम

कहीं जाते हैं कि हमारे पास दुनिया की नंबर एक मेट्रो है, हमारे पास दुनिया का एक नंबर का एयरपोर्ट है। आज ये हम इसको गर्व से कह सकते हैं। जो चीज स्टेबलिश हो गयी और तीस लाख लोगों को जो पर डे ट्रेवल करा रहे हैं। आज हम मेट्रो स्टेशन में जब एंटर करते हैं तो मैं इंडिविजुअली ये महसूस करता हूं, एक सिटिजन के रूप में कि जैसे मैं दिल्ली से बाहर गया, विदेश में आ गया। ये एक तरह का एनवायरन्मेंट मेट्रो ने दिया है, जो हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे दिल्ली में जो मेट्रो है, वो एक सिस्टमेटिक सिस्टम से चलने वाली एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब प्रश्न ये है कि जो तीसरा फेज सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी निभाती, मेरे पास कुछ डाक्यूमैंट भी हैं, सरकार अगर अपनी रिस्पोंसिबिल्टी निभाती तो डेढ़ साल पहले सौ किलोमीटर मुकुंदपुर से शिव विहार का पूरा एक अठावन किलोमीटर का स्ट्रैच है, इसमें से और इसके अलावा थर्ड फेज पूरा हो सकता था डेढ़ साल पहले। अब देखिये 2014 में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने, यहां हमारे साथी बैठे हुए हैं अजेश यादव, बादली से और सिरसपुर तक का ट्रैक सेंक्शन कर दिया और यानि की जो मेट्रो बादली पर खत्म हो रही है, वो एक स्टेशन सिरसपुर तक जायेगी कि मेरे पास पेपर है 2014, 08 अक्टूबर 2014 को ये सेंक्शन दी गई। ये मेरे पास दूसरा पत्र है दिल्ली मैट्रो का, जो पूछा कि ये क्यों नहीं आप इसको शुरू करते है जब आपके पास सैंक्शन आ गई है भारत सरकार की तो डीएमआरसी लिखता है फर्दर ये 9 सिंतबर, 2016 को लिखा और आज भी स्टेटस यही है। बादली से सिरसपुर शुरू नहीं हुआ, लास्ट लाईन पढ़ देता हूं पूरा लेटर पढ़ने की बजाय further approval of delhi government is yet to be received. Only after receipt of approval of Delhi Government, further necessary action in the matter can be taken by DMRC. जब तक दिल्ली की सरकार हमको सैंक्शन करके नहीं भेजेगी, डीएमआरसी इस पर एक्शन नहीं ले सकती।

इसलिए ये मन्डेटरी प्रोवीजन है। इसी एक्ट का कि ये जो मैट्रो का जो भी सैंक्शन होगा, फेज–4 है, फेज–4 जो है, वो बहुत इंपोर्टेंट है और फेज–4 में दिल्ली के वो तमाम इलाके बदरपुर, बवाना, नरेला, मौजपुर, भजनपुरा, तुगलकाबाद, मदनगीर, संगम विहार, वसंत कुंज, महिपालपुर, खजूरी खास यानि की आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र बवाना, नरेला अगर आप देखें, दक्षिणी दिल्ली का तो तुगलकाबाद और उसके बाद बदरपुर का इलाका और इधर मौजपुर हो गया, इधर भजनपुरा हो गया यानि कि मदनगीर हो गया, संगम विहार तमाम इलाकों में फेज–4 में मैट्रो को जाना है। ढ़ाई साल डिले हो गई ये। ढ़ाई साल क्यों, क्योंकि दिल्ली गर्वमेंट ने जो फाइनेंशियल अरेन्जमैन्ट हैं, फाइनेंसिस का जो इशू है, जो पहले तीन फेजिज में जिसको मैच्योर किया गया... मैं एक मिनट बोल लूं सर? मैं चाहूंगा मुझे बोलने दिया जाए तो अच्छा है।

अध्यक्ष महोदयः कोई और बात है, विषय तो ऐसा कुछ नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं यही चाहूंगा, मैं 5 मिनट लूंगा। मैं जो भी बात करूंगा तथ्यों पर आधारित करूंगा।

अध्यक्ष महोदयः तो कोई और विषय, आप तो डिस्टर्ब हो जाते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः तो सवाल ये है कि जब ढ़ाई साल ये पूरे 40 लाख और थर्ड फेज जुड़ेगा तो 50 लाख लोग ट्रेवल करेंगे और जैसे मैं रोहिणी रहता हूं। रोहिणी से मुझे अगर वेस्ट दिल्ली में जाना है पंजाबी बाग की तरफ या धौला कुंआ की तरफ तो मुझे पहले बस अड्डे आना पड़ता है या कनाट प्लेस आना पड़ता है लेकिन जब ये रिंग रोड, रिंग रेलवे की तरह ये जब कनेक्टिविटी होगी तो मुझे 30 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। मैं 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच

सकता हूं अगर ये थर्ड फेज चालू होगा तो लोगों का समय भी बचेगा और लोगों का किराया भी बचेगा लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वो देरी होता चला गया। फोर्थ फेज शुरू ही नहीं हो रहा। फोर्थ फेज शुरू होगा, कब होगा, इस पर मैं चाहूंगा जरूर उप मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी इस पर रिप्लाई करे। इसके बारे में बताएं? लेकिन अगर थर्ड फेज और फोर्थ फेज पूरा ही नहीं होगा...

अध्यक्ष महोदयः किराए पर तो आओ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं किराए से ही जोड़ रहा हूं सारी बातों को। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को, दिल्ली की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, उसके हालात आपने देखें हैं। ये हालात क्यों बने हैं, ये हालात दिल्ली में दस हजार बसें आपने लेनी थी, आज देखिए, दिल्ली में अगर बस की कनेक्टिविटी होती, मैं अभी देख रहा था, मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, बस जो है, लो फ्लोर बस, उसमें किराया 25 रूपये है, मैट्रो में आज की डेट में 30 रूपये है यानि कि बसेज अगर होती सारे शहर में तो मैट्रो पर इतना वजन ही नहीं पड़ता। मैट्रो आज भर के चल रही है। उसमें पूरी बुरी स्थिति है। वो स्थिति नहीं आती।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मैट्रो में तो एक लाख, डेढ़ लाख यात्री कम हो गया है। मई में डेढ़ लाख ऑन रिकार्ड है, डेढ़ लाख यात्री कम हो गया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं और वो ये है...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप किराए पर कुछ कहना चाह रहे है?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर आपने पिछले ढ़ाई साल में एक बस नई नहीं खरीदी। आप बताइये?

अध्यक्ष महोदयः अरे भई! 50 बसों का तो मैंने यहीं से उद्घाटन किया था विधान सभा से।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, पिछले ढ़ाई साल में, एक मेरी बात सुन लीजिए। आपने 2,000 बसेज खरीदी। चार फैसले मेरे पास हैं आपके। चार फैसले सरकार के हर बार डेफर हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदयः अच्छा! किराए पर आप क्या कह रहे है?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः किराए पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी बात, पूरे मामले को आज, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको विपक्ष से इतना डर क्यों है? आपने जगदीश को नहीं बोलने दिया, आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते। आप विपक्ष की बात सदन में क्यों नही आने देना चाहते?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः पूरे 15 मिनट हो गए विजेन्द्र जी, पूरे 15 मिनट। आप घड़ी मत देखिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे आप, देखें, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः हां, करिए आप। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं लेकिन उसको कन्कलूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः डीटीसी 3400 करोड़ रूपये सालाना घाटे पर है।

अध्यक्ष महोदयः अब आप किराए पर आईये सीधा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉलेप्स हो गया है दिल्ली में, उसका कारण ये है कि दिल्ली की बस सेवा पूरी तरह सरकार के शासन काल में ध्वस्त हुई है अगर दिल्ली में बस सर्विसेज होती प्रॉपर, तो आज जो स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति पैदा नहीं होती। आप क्या समझते है कि मैट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो बस...

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, एक बात बताओ, एक बात प्लीज? बस से मैट्रो के किराए का क्या लेना देना है? मैट्रो का किराया बढ़ेगा तो बस पर और लोड आएगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं अध्यक्ष जी, एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, विषय से भटक रहे है, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कि जो बात,

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप विषय को नहीं लेना चाह रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप बात ही नहीं करने देना चाह रहे है। आप इनको रोकिए।

अध्यक्ष महोदयः 15 मिनट तो आपने जितनी बात की है, 15 मिनट.

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं सारी बात बता रहा हूं आपको।

अध्यक्ष महोदयः वो बेकार की है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं उसको पूरा कर देता हूं।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप एक बात समझ लीजिए जो एफएफसी है.

अध्यक्ष महोदयः समय भी देख लीजिए अब।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, बैठिये प्लीज, समय खराब हो रहा है।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या तरीका है तुम्हारा, बैठिए आप, बैठिए आप

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, भाई साहब। चर्चा जिस विषय पर हो रही है, हम जा रहे हैं दूसरे विषय पर। मैंने पूरा समय दे लिया है, पूरे आपने आंकडे आंक लिए हैं। बस के आंकड़े रख लिए, मैट्रो के आंकड़े रख लिए, किराए पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आप।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात कहने दी जाए। घबराइये मत, घबराइये मत। जनता के बीच में सारा सच जाने दीजिए। अब आप आइये, फेयर फिक्सेशन कमिटी ये....

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, क्या है ये?

अध्यक्ष महोदयः आप बोलिए, बोलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, उनको बिठाइये आप।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप लोगों ने भी एक घंटा परेशान किया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः किनको?

अध्यक्ष महोदयः अनिल बाजपेयी जी को बोलने नहीं दिया। अनिल बाजपेयी जी को बोलने नहीं दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप समय वेस्ट करवा रहे हैं, तो करवाइये।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, ये कोई तरीका नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप बात ही नहीं पूरी करने देना चाह रहे है। आप विपक्ष को मौका ही नहीं देना चाहते।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्योंकि आपकी पोल खुल रही है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, बैठिए, बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बैठिए, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिए, आज किराए पर चर्चा हो रही है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये चर्चा करवा रहे है आप!

अध्यक्ष महोदयः और वो किराए की चर्चा से भाग रहे हैं, कुछ तो समझिए मेरी आज...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरी बात को, मैट्रो के बारे में, लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप यहां पर सदन में मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं ये बात ठीक नहीं है। अगर मैट्रो पर सही बात मैं रखना चाहता हूं तो मुझे रखने दी जाए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे अपनी बात रखनी दी जाए अध्यक्ष जी, एक बार अपनी बात कहने दी जाए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, एक सैकेंड।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, बात तो सुनिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे मत रोका जाए। मैं मैट्रो पर अपनी बात कहना चाहता हूं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सही राम जी, बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप दिल्ली मैट्रो को खराब करना चाहते है, दिल्ली मैट्रो बर्बाद करना चाहते है आप, दिल्ली की मैट्रो में पॉलिटिक्स घुसाना चाहते हैं आप। अब मुझे मेरी बात कहने दी जाए। मुझे मेरी बात कहने दी जाए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, उनको बिठाइये आप।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, ये बात ठीक नहीं। नितिन जी बैठिए प्लीज, नितिन जी बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात कहने दी जाए। मैट्रो पर मुझे अपनी बात कहने दी जाए। देखिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक बात आप समझ लीजिए जो अध्यक्ष जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ऐसा है, वो सदन छोड़कर चले जाएंगे। किराए का कहलवाना है इनसे, मैं कहलवा कर छोड़ूगा किराए के बारे में। हां, बोलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा इतना कहना है कि लोगों को गुमराह मत करिए। मेरे पास डीएमआरसी का एक्ट है।

अध्यक्ष महोदयः अरे भई! एक्ट हो गया, सारा हो गया। एक्ट आपने पढ़ लिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं यही बता रहा हूं आपको।

अध्यक्ष महोदयः पूरा समय आपको दे दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः अब जो विषय है, उस पर आ जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हां, विषय पर ही बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः हां, बताइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः विषय ये है कि जो फेयर फिक्सेशन कमिटी है,

अध्यक्ष महोदयः वो आ गई, आपने बोल दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः वो फेयर फिक्स करती है तो उसका जो आधार होता है ऑपरेशन। ऑपरेशनल लॉसिस जो भी ऑपरेशनल लॉसिस होंगे, ये इसी डीएमआरसी एक्ट में लिखा हुआ है और ये जो सैंक्शन होते हैं प्रोजेक्ट, उस पर भी ये एक बाइंडिंग्स है स्टेट गर्वमेंट पर कि जितने भी ऑपरेशनल

लॉसिस होंगे, उसकी रिस्पोन्सिबिल्टी स्टेट गवर्नमेन्ट की होगी, ये मैटो के एक्ट में है, ये मैट्रो की व्यवस्था में है। अब आ गई बात किराए की। किराए में ओपरेशनल लोसेज, ओपरेशनल लोसेज जो भी उसमें डैफिसैंसी आती है, जो जरूरते हैं, ये तो यहां सदन में कोई नहीं चाहेगा कि मैट्रो को डैफिसैंसी में रखा जाए, मैट्रो को फाइनैंसियल क्राईसिसज में रखा जाए, उसकी सर्विसिज पर, लोगों की जिन्दगी पर उसका असर पड़े, ये तो कोई नहीं चाहेगा। हम चाहते हैं कि मैट्रो की फैसलिटी रहे। एक सैकंड....

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप दिल्ली की जनता के ऊपर अन्याय कर रहे है। आप अन्याय कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप बात को सुनना ही नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदयः आप अन्याय कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं फाइनैंसियल लॉसेज की बात कर रहा हूं, जो भी, अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष महोदयः भई, आज सीधा सा था मैट्रो का किराया बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं चाहता हूं कि जो भी लॉसेज हैं, जो भी दिल्ली स्टेट गवर्नमेन्ट को, उन ओपरेशनल लॉसेज को, उन ओपरेशनल लॉसेज को अगर आप सिर्फ भाषण के लिए भाषण करा रहे हैं, तर्कसंगत चर्चा यहां नहीं करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आप दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, मैट्रो के साथ अन्याय कर रहे है। ऑपरेशनल लॉसेज...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः दो मिनट, मंत्री जी जवाब देंगे ना। आप बैठिए दो मिनट, नितिन जी। बैठिए, जरनैल जी प्लीज, मंत्री जी जवाब देंगे अपने आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जो भी ऑपरेशनल लॉसेज हैं, वो आप हन्ड्रैड परसैंट, मेरा इतना कहना है।

अध्यक्ष महोदयः ऑपरेशनल लॉसेज के विषय में क्या कहना है?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ऑपरेशनल लॉसेज जो है, वो स्टेट गवर्नमैन्ट की रिस्पोंसिबिल्टी है, अगर गवर्नमैन्ट ये कहती है कि हम सब्सिडी देना चाहते हैं तो आपको हन्ड्रेड परसैंट सब्सिडी देने की आज यहां पर प्रस्ताव पारित करना चाहिए। कोई भी सब्सिडी आप देना चाहते हैं उसको आप पार्शली नहीं कह सकते क्योंकि ऑपरेशनल लॉसेज, हम सरकार से कहेंगे, सरकार तीन हजार करोड़ रुपया दे पूरा, हर साल और दिल्ली के अंदर जो पूरा विकास का मार्ग आपने ब्लॉक कर दिया है, जो दिल्ली के अंदर बसेज नहीं हैं, यूनिफाइड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम नहीं है। दिल्ली के अंदर व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। आप दिल्ली को एक मैच की तरफ ले जाना चाहते हैं इसलिए ऑपरेशनल लॉसेज पूरे करना, वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार तीन हजार करोड़ रुपये की पूरी की पूरी दे, क्योंकि 10 स्टेटस के अंदर मैट्रो है, बैंगलोर के अंदर है, लखनऊ के अंदर है, जयपुर के अंदर है जो कलकत्ता की मैट्रो है, वो रेलवे का प्रोजैक्ट है, वो सैंट्रल गवर्नमैन्ट का प्रोजैक्ट है, उसका स्टेट गवर्नमैन्ट से कोई लेना–देना नहीं है। ये आप समझ लो, वो प्योरली सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट का प्रोजैक्ट है और मैट्रो कलकत्ता, उसके लॉसेज जब आप तीन हजार करोड़ रुपया आप डीटीसी में दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, आप बैठिए। चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः अब विजेन्द्र जी, कन्कलूड हो गया, विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः तीन हजार करोड़ पूरे दीजिए आप।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए, बैठिए प्लीज। चलिए, प्लीज, छोड़ दीजिए। नहीं, वो कह रहे है, क्लीयर हो गई बात, राजेन्द्र पाल गौतम जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी, खड़े हो गए हैं। भई सौमनाथ जी, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, सदन ऐसे नहीं चल पाएगा, प्लीज। नहीं, मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं। बैठिए, मंत्री जी, जवाब देंगे ना जी। अभी दे रहे हैं जवाब दो मिनट रूकिए।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम, मंत्री (समाज कल्याण मंत्री): बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दिया।

वैसे तो हमारे सारे सम्मानित विधायकगण ने पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है कि कब–कब, कितना–कितना किराया बढ़ा, वो भी रखा है, लेकिन मैं उन तथ्यों को दोहराऊंगा नहीं। लेकिन इस किराए के बढ़ने से एक आम आदमी किस तरह प्रताड़ित है और आम आदमी तो छोड़िए हम एमएलएज और मंत्री भी किस हद तक प्रताड़ित हैं, वो मैं छोटा सा तथ्य सिर्फ आपके सामने रखूंगा। मेरे दो बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते है, मेरी वाईफ भी स्कूल जाती है, तीनों को मैं सुबह पहले छोटे बेटे को मैट्रो पे छोड़ता हूं, अपनी गाड़ी से उसके बाद अपनी वाइफ और अपने बड़े बेटे

को छोड़ता हूं। मेरा छोटा बेटा इस मैट्रो से कश्मीरी गेट से दिलशाद गार्डन जाता है। वहां से फिर रिक्शे से अपने स्कूल जाता है, पहले अपनी वाइफ को 1500 रुपए महीना मैं किराए के लिए देता था। अब से चार महीने पहले, बड़े बेटे को ढ़ाई हजार रुपए महीने देता था और अपने छोटे बेटे को 15 सौ रुपए महीना देता था, साढ़े पाँच हजार रुपया केवल मैं किराए के लिए देता था, लेकिन जब ये मई 2017 में किराया बढ़ा उसके बाद वाइफ को मैं दो हजार रुपए किराए के लिए दे रहा हूं और बड़े बेटे को चार हजार रुपए दे रहा हूं और छोटे बेटे को दो हजार दे रहा हूं जो साढ़े 5 हजार रुपए किराया लगता था, वो किराया अब बैठ गया 8 हजार रुपए महीना। 2011 में एमएलएज की, मंत्री की पहले तनख्वाह बढ़ी थी, इसके बाद लगभग 6–7 सालों में, हंसने की बात नहीं है, हम पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारा दर्जा जो चीफ सेक्रेटरी के रैंक के बराबर है, सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज की 2011 में अब से आधी तनख्वाह थी, वो 2017 तक आते–आते दुगुनी हो गई है। सब्जी के दाम भी बढ़ गए हैं, नोटबंदी ने सब कुछ क्रश करके रख दिया, जीएसटी ने बचा, रहा–सहा वो भी खत्म कर दिया। ये जितना भी केन्द्र की सरकार एक–एक करके फैसले ले रही है, ये फैसले किस तरह देश की गरीब जनता को, दिल्ली के लोगों को, और तो ओर अब हम सब एमएलएज और मिनिस्टर्स को भी क्रश कर रही है, मैं ज्यादा इस मुद्दे पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस मुद्दे पर हमारे सारे विधायकों ने अपनी–अपनी बात रख दी है, लेकिन मैं ये जरूरी कहना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार को फैसले लेने से पहले जनता के बारे में सोचना चाहिए कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। इस हालात में जिस तरीके से मंहगाई बढ़ रही है, पैट्रोल का, क्रूड ऑयल का दाम देख लीजिए, जब यूपीए गवर्नमैन्ट थी, 140 डॉलर प्रति बैरल के आसपास तक पहूंच गया था और उस वक्त मार्केट के अंदर यहां पे पेट्रोल

76 रुपए मैक्सीमम रेट हुए। जो 140 से घटके पिछले दिनों 30 डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम आ गए। उसके बाद भी हमें आज भी जो अब लगभग 50–54 के आसपास है और उस हिसाब से पेट्रोल के दाम अब 80 तक पहुंच गए है, दिल्ली में भी 72–73 रुपए के आसपास है, मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम कोई भी निर्णय केन्द्र की सरकार लेती है तो सारे तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए लोगों की इन्कम कितनी है, उसको ध्यान में रखना चाहिए और उसी हिसाब से एक्सपैंडिचर बढ़ना चाहिए। इसी तरह एक्सपैंडिचर अगर बढ़ाते रहे, इसी तरह अगर खर्चे बढ़ाते रहे तो सब लोगों का हाल क्या होगा, दिल्ली के लोग कैसे रहेंगे, आप खुद जाके देखिए। मैं कई दफे जाता हूं मैट्रो में आप कभी जाके, कनाट पैलेस से नीचे उतरके यहां आने के लिए मैट्रो पकड़ना, आपको अहसास होगा मैट्रो की लाइन में खड़े होंगे आप अपने पैर से चले बिना, अपने आप उठाके अंदर रख दिएं जाएंगे, ये हालात है मैट्रो की, उसके बाद किराया इतना ज्यादा बढ़ रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुप्ता जी, आप प्रवक्ता हैं क्या? आप मैट्रो के प्रवक्ता की भूमिका न निभाएं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जवाब देंगे, मंत्री अभी जवाब देने वाले हैं।

समाज कल्याण मंत्रीः मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, जब वो नितिन जी बोल रहे थे, आपको परेशानी हो रही थी। अब क्या तमाशा है ये? नहीं, क्या तमाशा है ये? देंगे जवाब आएगा उनसे, चलिए।

समाज कल्याण मंत्रीः और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं माननीय

मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को इतनी गम्भीरता से लिया और एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी 50 परसैंट शेयर को जो 15 सौ करोड़ देने का एलान किया, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और निवेदन करना चाहूंगा केंद्रीय सरकार से कि वो भी अपने हिस्से के 1500 करोड़ दें और दिल्ली की जनता को राहत दें, बहुत–बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री सोमनाथ भारतीः सदन के अंदर जो बोलने का समय सीमा है, वो हर पार्टी के स्ट्रैंग्थ से फैसला होता है, इस वक्त भाजपा के दो सदस्य हैं, दोनों ने बोल लिया। हमारे छः सदस्य ने बोला ओर बोलना चाहते हैं। आप रोकना चाहते हैं उसको? एक मिनट रूकिए आप।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिए विजेन्द्र जी, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है आपका बात करने का। ये कोई तरीका नहीं है विजेन्द्र जी। नहीं आप, तहजीब नहीं आपको, आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कोई तरीका है ये, नहीं कोई तरीका है ये बात करने के। भई सोमनाथ जी, ये विषय की चर्चा जो है।

सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष जी, मैं बड़ी नम्रता से बात रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, ये विषय की चर्चा जो है, वो बड़ी गंभीर है। ये खत्म हो जाएगा।

श्री सोमनाथ भारतीः आपने उनकी मान–मर्यादा रखते हुए विपक्ष के नेता ने बोला, विपक्ष के नेता ने अपने साथियों को बुलवा लिया। हमारे तरफ से छः साथियों ने बोला हममे से और कोई बोलना चाहता है, आप बोलने नहीं देना चाहते।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, बैठिए प्लीज। मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय,

... (व्यवधान)

प्रोप्रोर्शनिज्म का प्रिंसिपल हर जगह होता है यहां भी लागू होना चाहिए आप उनको अनलिमिटेड बोलना देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदयः ऐसा है, आप मेरी बात सुनें भैया, वो केन्द्र सरकार है। अरे भई सुन तो लो एक बार! सोमनाथ जी, बैठिए प्लीज। वहां केन्द्र सरकार है, लोकतंत्र नहीं है। यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोकतंत्र है। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। बैठिए तो सही, बैठ जाओ। बैठ जाओ प्लीज। नहीं अब बैठ जाइए प्लीज रिक्वेस्ट है। सोमनाथ जी, देखिए, बैठिए। मैं हमेशा समय देता हूं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ रहा हूं। अध्यक्ष की कुर्सी से हाथ जोड़ रहा हूं, बैठिए। समय का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। हां, माननीय मंत्री, कैलाश गेहलोत जी।

परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर मुद्दा है। सम्मानित सदस्यों ने काफी अपने–अपने विचार रखे और जो फैक्ट्स सबने रखे, उनको न दोहराते हुए, शुरूआत करना चाहूंगा। जिन मुद्दों पर चर्चा की विजेन्द्र गुप्ता जी ने और मैं डिप्टी सीएम साहब से बिल्कुल सहमत हूं। डिप्टी सीएम साहब बार–बार कहते हैं कि विजेन्द्र गुप्ता जी कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। कहीं न कहीं उनके तथ्यों में हमेशा गड़बड़ होती है और जो बात कहते हैं कि फैक्ट्स पर मैं बात कर रहा हूं, कानून की बात कर रहा हूं, उनमें हमेशा की तरह आज भी इन्होंने इस असेम्बली को

गुमराह किया, सभी सदस्यों को गुमराह किया और पूरी दिल्ली की जनता को भी गुमराह किया। सबसे पहले विजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा कि डीएमआरसी के चेयरमेन को एप्वाइंट करने की पॉवर जो है, दिल्ली सरकार की है तो जो रेलिवेंट दिल्ली मेट्रो के जो आर्टिकल हैं, उसको अगर पढ़ा जाए और मैं पढ़ना चाहूंगा ताकि सबको ये चीज क्लीयर हो तो आर्टिकल–139 सर टॉक्स अबाउट कि चेयरमेन की नियुक्ति कैसे होगी He says chairman of the board of Directors shall be…

... (व्यवधान)

परिवहन मंत्रीः आप तो पढ़कर आए हैं सारा ढूंढ लीजिए अपने आप।

अध्यक्ष महोदयः अभी बताया उन्होंने रिपीट किया एक बार सेक्शन दोबारा बता दीजिए।

परिवहन मंत्रीः सेक्शन नहीं आर्टिकल है। डिफरेंस है दोनों में थोड़ा सा। तो आर्टिकल–139 स्पीकर साहब टॉक्स अबाउट अपाइंटमेंट आफ चेयरमेन और जो शब्द यूज किया गया है वो shall है may नहीं है और उम्मीद करता हूं कि विजेन्द्र गुप्ता जी को मे और शेल में भी अंतर पता होगा। The chairman of the board of Directors shall be a nominee of central Government. तो ये बात बिल्कुल गलत absolutely false और ये बात जानबूझकर आपने चेयरमेन के बारे में....

... (व्यवधान)

परिवहन मंत्रीः वो चेयरमेन नहीं, एमडी है। आपने चेयरमेन की बात की है, आप रिकार्ड चेक कीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आपने फेयर फिक्सेशन। देखिए विजेन्द्र जी, दो मिनट बैठिए। विजेन्द्र जी, बात सुन लीजिए। विजेन्द्र जी, आपने फेयर फिक्सेशन की आपने बात की फेयर फिक्सेशन कमेटी की। आपने बात की फेयर फिक्सेशन कमेटी की। उसी की वो बात कर रहे हैं। चलिए बताइए आप।

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः सर, दिस इज बेड सर, सर ये किसी विधायक को नहीं बोलने देते, किसी मंत्री को नहीं बोलने देते सर, गुंडागर्दी मचा रखी है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए प्लीज। चलिए। नितिन जी बैठिए प्लीज। भई देखिए, विजेन्द्र जी, आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो आपको परेशानी होती है। उनको हक है ना अपनी बात कहने का। सदन का तमाशा मत बनाइए आप। आप नेता विपक्ष हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जिम्मेवारी से बात करिए। बैठिए नितिन जी, बैठिए प्लीज। एक घंटा सदन का इसी बात पर खराब हो जाता है। अब नितिन जी, बैठिए, प्लीज। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कैलाश जी को।

... (व्यवधान)

परिवहन मंत्रीः सर ये क्लीयर होता है कि चेयरमेन जो डीएमआरसी के है, वो सेन्ट्रल गर्वमैन्ट के नॉमिनी है और जहां तक मैनेजिंग डायरेक्टर की बात है, वो तो बार–बार हम अपने पत्रों में दोबारा कह रहे हैं कि जो

एमडी है, वो दिल्ली सरकार का नॉमिनी है, उसमें कहां डाउट है? हम तो खुद पत्र लिख रहे हैं बार–बार, कुछ मीटिंग बुलाई चीफ सेक्रेटरी...

... (व्यवधान)

परिवहन मंत्रीः भई मुझे बोलने दो आप।

अध्यक्ष महोदयः भई आप दो मिनट चुप हो जाइए। विजेन्द्र जी, आप चुप हो जाइए। ये कोई तरीका नहीं है। विजेन्द्र जी, आज आपकी दुखती नस पर हाथ रख दिया है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। आपकी दुखती नस पर हाथ रखा गया, आप इसलिए परेशान हो रहे हैं। आप दिल्ली की जनता का हित नहीं सोच रहे हो और इसलिए आपको परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कुर्सी में कीलें लग गई हैं, बैठ जाइए आप चुप। चलिए आप करिए–करिए।

परिवहन मंत्रीः स्पीकर सर, इनको ये भी पता होना चाहिए कि एमडी के ऊपर चेयरमेन है और अगर ये कह रहे हैं तो अभी कुछ बताऊंगा जो चेयरमेन साहब लिखा है, आज और वो बिल्कुल साफ करता है कि....

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई विजेन्द्र जी, आप क्या बात कर रहे हैं, कोई तमाशा है यहां?

परिवहन मंत्रीः हमने बिल्कुल फेवर नहीं किया।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मुझे मजबूर होना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आप बार–बार टोक रहे हैं। नहीं, आप बार–बार टोक रहे हैं। आप बार–बार मंत्री को टोक रहे हैं। कोई तमाशा है? ये तहजीब नहीं है आपको। बार–बार

मंत्री को टोक रहे हैं आप। वो जो बोल रहे हैं, मैं सारा सुन रहा हूं। चलिए।

परिवहन मंत्रीः सर, एमडी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई जरनैल जी, प्लीज।

परिवहन मंत्रीः सर, दिल्ली सरकार ने अभी नहीं, बार–बार जब से फेयर फिक्सेशन कमेटी कंस्टीट्यूट हुई 27 मई को। कमेटी कंस्टीट्यूट हुई 17. 6 को कमेटी ने ऑब्जेक्शन इन्वाइट किए 30 जून को। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये व्यूज रखे गए कि हम इस हाइक के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। 8 सितम्बर को फेयर फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट आई और तब से लेकर आज तक बार–बार चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुए, चाहे डिप्टी सीएम हुए, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हुए, बार–बार हर कदम पर ये केन्द्र सरकार को याद दिलाया कि अगर हाइक होगा...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई फिर वहीं बात। विजेन्द्र जी, ये तो कोई तरीका नहीं है। क्या बात कर रहे है?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, ये ठीक नहीं है। विजेन्द्र जी, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, विजेन्द्र जी ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नहीं ये गलत तरीका है आपका बहुत गलत तरीका है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अरे! केन्द्रीय मंत्री खुद कह रहे हैं कि किराया बढ़ेगा। आपको पता नहीं, क्या परेशानी हो रही है! तो क्या? आप केन्द्रीय मंत्री को रोको ना।

परिवहन मंत्रीः तो आप चाहते हो फेयर बढ़े, नहीं, आप चाहते हैं फेयर बढ़े?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, विजेन्द्र जी, ये ठीक नहीं है प्लीज।

परिवहन मंत्रीः नहीं, आप क्या चाहते हैं फेयर बढ़े?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आपने सदन का मजाक बना दिया। मैं बता रहा हूं। इतना गलत व्यवहार किसी भी विपक्ष के नेता का मैंने नहीं देखा आज तक। आपने सदन का मजाक बना दिया। बैठ जाइए आप नीचे। अब मंत्री जी बार–बार, इतना तो कम से कम लिहाज करिए सदन का। सब्जी मंडी बना दिया है आपने और आप बोले तो ठीक नहीं होगा। कॉमेडियन की तरह से आप नाच रहे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी बैठिए, सोमनाथ जी। सोमनाथ जी वो चाहते हैं, मैं इनको बाहर करूं और मैं इनको बाहर नहीं करूंगा। आप बैठिए, वो चाहते हैं, बाहर करें। मैं इनको बाहर नहीं करूंगा, बैठिए। आप कॉमेडियन की तरह से नाच रहे हैं कोई तरीका है ये। एक जैसे मदारी बार बार खड़ा हो जाता है, वैसे खड़े हो रहे हैं बैठिए आप। बैठ जाइए आप। कोई तरीका है ये? ये आपने तानाशाही बना रखी है। मंत्री जी को आप बोलने नहीं दे रहे। क्या मंत्री जी गलत बोल रहे हैं? चलिए।

परिवहन मंत्रीः स्पीकर सर।

... (व्यवधान)

परिवहन मंत्रीः स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान इसपे भी दिलाता हूं कि विजेन्द्र गुप्ता जी ने जिस सैक्शन का जिक्र किया। जिसमें ये कह रहे हैं कि फेयर फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट बाइंडिंग है, तो मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि बाइंडिंग का मतलब क्या है। तो क्या बाइंडिंग का मतलब है कि रिपोर्ट का एक हिस्सा उठा के उसको इम्पलीमेंट कर दिया। रिपोर्ट के दूसरे हिस्सों को उठाकर जब बोर्ड का मन किया, तब उठा के इंपलीमेंट किया। जिस सेक्शन–37 का जिक्र किया इन्होंने, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि रिपोर्ट की फाइंडिंग और रिपोर्ट कमेटी की फाइंडिंग और रिपोर्ट बाइंडिंग है। लेकिन उसी कमेटी ने ये भी कहा कि अगर फेयर बढ़ेगा तो फेयर जो है, वो एक साल के ड्यूरेशन में बढ़ेगा। एक साल के इंटरवेल में बढ़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं कमेटी, ये कमेटी....

अध्यक्ष महोदयः भाई विजेन्द्र जी, आप बोल रहे हैं?

परिवहन मंत्रीः कुछ तो आप शर्म करो, कुछ तो शर्म कीजिए। क्या आपने....

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मैं एक बात कह रहा हूं। मंत्री जी सदन में स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको अगर कुछ गुमराह कर रहे हैं, लगता है। सदन में स्टेटमेंट है आप बाद में राइटिंग में दे दीजिए, वो सदन में स्टेटमेंट आ रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। आप बार बार उनको जानबूझकर डिस्टर्ब

कर रहे हैं। आपको अगर गलत लगता है। आप बैठिए, प्लीज। बैठिए आप, बैठ जाइए। चलिए।

परिवहन मंत्रीः कमेटी, एक तरह से कमेटी ने कहा कि फेयर अक्टूबर, 2016 में बढ़ेंगे और फिर अगर बढ़ेंगे तो एक साल के इन्टरवेल के बाद अक्टूबर, 2017 में बढ़ेंगे। लेकिन बोर्ड को किसने अधिकार दिया कि जिस कमेटी ने कहा कि अक्टूबर, 2016 से रेट बढ़ेंगे, वहां आठ महीने तक बोर्ड की मीटिंग नहीं होती है ये कौन सा कानून था?

अध्यक्ष महोदयः कार्पोरेशन के चुनाव होने थे इसलिए नहीं हुआ।

परिवहन मंत्रीः और कौन सा कानून था ये? तो क्या तब जो रिपोर्ट बाइंडिंग की तब उनको समझ में नहीं आया!

अध्यक्ष महोदयः मुझे आज बहुत पीड़ा हो रही है, आज बहुत पीड़ा हो रही है।

परिवहन मंत्रीः ये कौन सा कानून था?

अध्यक्ष महोदयः मैं इतना पीड़ित हूं आज, कह नहीं सकता हूं। मैं अभी अभी बताऊंगा, अभी बताऊगा मैं।

परिवहन मंत्रीः विजेन्द्र गुप्ता जी को, मुझे लगता है कि डीएमआरसी का वकील बन जाना चाहिए, बिल्कुल, वकील बन जाना चाहिए उनको। विजेन्द्र गुप्ता जी चुने हुए, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन उनको करोड़ों आदमियों की चिंता नहीं है। लेकिन डीएमआरसी ने क्या किया, चेयरमैन ने क्या किया, उसकी बहुत चिंता है विजेन्द्र गुप्ता जी को। हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो बोर्ड में मीटिंग हुई, बोर्ड में लगातार मीटिंग हुई लेकिन ये एजेंडा, उसमें क्यों नहीं रखा गया, ये डीएमआरसी से पूछा जाए और

बिल्कुल यही चीज पूछने के लिए बार बार मीटिंग बुलाई। सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई। चीफ सैक्रेटरी साहब यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भई, हम दिल्ली सरकार के नॉमिनेट डायरेक्टर्स हैं और अभी मैं आपको वो कानून भी दिखाऊंगा कि जिसमें कहा गया... आर्टिकल तो डीएमआरसी के हैं। उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी डॉयरेक्टर बोर्ड मीटिंग कनवींन करेगा तो वहां भी जो शब्द यूज किया है, वो शेल है, में नहीं है। इसका मतलब की आर्टिकल में जो लिखा गया है, वो बाइंडिंग है। लेकिन 4 अक्टूबर से लेके आज 9 अक्टूबर हो गई, बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई, इसका जवाब विजेन्द्र गुप्ता जी के पास नहीं है। जा के डीएमआरसी से पूछ लें जा के कि क्यों नहीं बुलाई गई और अपने चेयरमैन जो यूडी के सैक्रेटरी हैं, उनसे पूछें। तो स्पीकर सर आर्टिकल 138....

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए, आप बोलते रहिए। उनको बोलने दीजिए।

परिवहन मंत्रीः आर्टिकल 138 कहता हैः when meeting to be convened. The Secretary shall of DMRC और यहां भी शब्द जो प्रयोग किया गया है वो शेल है Secretary shall as and when directed by directors to do so, convene a meeting of the board by giving a notice in writing to every director. तो ऐसी क्या घबराहट है कि बोर्ड की मीटिंग तक नहीं बुला रहे और हम मांग क्या रहे हैं स्पीकर सर! पूरी दिल्ली की जनता मीडिया की रिपोर्ट के द्वारा पढ़ रही है, हम क्या मांग रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भई, अगर हम डीएमआरसी में 50 परसेंट के ओनर हैं और हमारे पाँच नॉमिनी डॉयरेक्टर बोर्ड पर हैं, तो हमारा ये अधिकार बनता है कि अगर कहीं, किसी भी निर्णय ने जनता को पीड़ा हो रही है। छः महीने के अन्दर लगातार दो बार जो किराया बढ़ाया जा रहा है और अगर आप जिस तरीके

से किराया बढ़ाया गया है, उसको देखें तो 114–115 परसैंट तक किराया बढ़ रहा है। तो दिल्ली सरकार क्या मांग रही है? दिल्ली सरकार कह रही है कि भई, जब तक बोर्ड की मीटिंग न हो जाए और उसमें ये सारी चीजें सामने न आएं कि दिल्ली सरकार ने जो ओब्जेक्शन किया कि ये किराया न बढ़े, उसको बोर्ड ने किस तरीके से ट्रीट किया?

दूसरी बात, फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट खुद कहती है कि जो प्रोपर्टी डीएमआरसी के पास है और फिक्सेशन की रिपोर्ट ने बार बार इसमें पूरा जिक्र किया है, किसी एक या दो कन्ट्री का नहीं, टोकियो का उन्होंने एक्जामपल दिया है, हांगकांग मैट्रो का एक्जामपल दिया है और जिन देशों में मैट्रो चल रही है कि वहां बिना फेयर बढ़ाए कैसे मैट्रो एफिशिएंटली और प्रोफिटेबल वेन्चर है, उसका एक्जामपल दिया। उसमें कहा कि भई, जितनी प्रोपर्टी डीएमआरसी के पास है। उसको बढ़िया तरीके से यूज करें, उसको बढ़िया तरीके से डेवलप करें। उसको किराए पे दें और वहां से जो आमदनी आए, उससे मैट्रो को रन करें, जिसको वो नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू कह रहे हैं। तो ये तो सबसे आसान काम है स्पीकर सर, कि अगर वो ऑपरेशन लॉस की बात करें कि ऑपरेशन लॉस हो रहा है और जब भी उस ऑपरेशन लॉस को कवर करना है, तो किराया बढ़ा दें, तो बहुत आसान काम है। 50 परसेंट जो है, वो दिल्ली सरकार से पैसा ले लें और केन्द्र सरकार से ले लें और जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की और जब हम बात करते हैं कि कैसे रेवेन्यू बढ़ाया जाए तो उसके बारे में कोई जवाबदेही नहीं है मैट्रो की। जब मन किया जब उठा के आप किराया बढ़ा दें। वहां से रेवेन्यू जनरेट करें तो ये तो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है स्पीकर सर। ये बिल्कुल गलत है and it is absolutely wrong. ये अगेंस्ट जो आब्जेक्टिवस हैं, जिससे कि ये मैट्रो डीएमआरसी बनाया गया। मैट्रो का ओब्जेक्टिव ये

नहीं था कि इसको वर्ल्ड क्लास एक प्रोफिटेबल वेन्चर बनाना है। वर्ल्ड क्लास, हम तब मानेगे जब इसमें लाखों लोग अपना निजी वाहन अपना पर्सनल व्हीकल छोड़कर हम मैट्रो में उसकी यात्रा करेंगे। तब हम उसको वर्ल्ड क्लास मानेंगे।

अभी कुछ मैट्रो के अधिकारियों को बुला के कुछ समझना चाहा मैंने कि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट जो फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट में लिखा, उसको भी आज नौ महीने हो गए हैं, तो उसमें उन्होंने क्या किया! लगातार 2006 से लेके 2016–17 तक? केवल 413 करोड़ रुपया कमाया मैट्रो ने सिर्फ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के हजारों करोड़ की रियल स्टेट दिल्ली सरकार की जमीन जो आज मैट्रो के पास है, उसकी जवाबदेही मैट्रो के पास है स्पीकर सर। उसी जवाबदेही डीएमआरसी की अकाउंटेबिल्टी डीएमआरसी की आंसरेबिल्टी इस पूरी दिल्ली की जनता की तरफ है और अगर हम फेज वाइज जो बात करें तो मैट्रो का टारगेट पहले फेज में 300 करोड़ था। फेज टू में जो 2005 से 2010, 960 करोड़ था, स्पीकर सर, 960 करोड़ और उसके मुकाबले सिर्फ 209 करोड़ रुपए मैट्रो ने प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से कमाया। दैट्स ऑल।

इसका जवाब कौन देगा? फेज–तीन में 2011 से 2016, 1586 करोड़ रुपए इन्होंने टारगेट रखा कि प्रॉपर्टी डवलपमेंट से वो कमाएंगे और 370 करोड़ का सिर्फ टारगेट अचीव हुआ। फिक्सेशन कमेटी रिपोर्ट ने खुद एक्जामपल दिया है हांगकांग मैट्रो का, जिसमें कि ये सात हजार करोड़ रुपया हांगकांग मैट्रो ने रेवेन्यू कमाया प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से। ताकि किराया बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े। तो लगातार बार बार दिल्ली सरकार के कहने के बाद भी अगर डीएमआरसी और केन्द्र सरकार मैट्रो बढ़ाने पर एडमेंट है तो मुझे पूरा यकीन है कि जो बार बार माननीय सदस्यों ने भी कहा कि ये कहीं न कहीं दिल्ली की जनता के साथ षड़यंत्र है और जान बूझकर

अक्टूबर, 2016 में किराया नहीं बढ़ाया गया ताकि आम आदमी की जेब पर ये एक दम बोझ न पड़े और ये तो दीवाली पूरा सबसे बड़ा हमारा त्यौहार है, फेस्टिवल है। उसके बिल्कुल नजदीक जहां लोग अपने–अपने घरों के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए अलग–अलग चीजें तोहफा देते हैं। वहां केन्द्र सरकार ने बहुत बढ़िया तोहफा दिया है दिल्ली की जनता को। माननीय सी.एम. साहब ने चिट्ठी लिखी थी यू.डी. मिनिस्टर को कि दिल्ली की जनता बिल्कुल तैयार नहीं है इस हाईक के लिए। इस हाईक को सी. एम. साहब ने बार–बार कहा कि ये एन्टी पीपल है और उसके जवाब में केन्द्र सरकार के मंत्री ने अपने ही अन्दाज में जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है केन्द्र सरकार में लेकिन यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। केन्द्र सरकार ने सिर्फ इतना कहके छोड़ दिया कि अगर दिल्ली सरकार ये चाहती है कि किराया न बढ़े, तीन हजार करोड़ रूपया देने के लिए तैयार है हर साल?

स्पीकर सर, एक तरफ हम बात करते हैं फेडरलिज्म की। एक तरफ हम बात करते हैं डीएमआरसी में 50–50 परसैन्ट पार्टनरशिप की। फिर दूसरी तरफ केन्द्र सरकार हमें ही धमकी दे रही है। तो इससे एक चीज साफ होती है कि यहां पर जो बीजेपी के सदस्य हैं और केन्द्र सरकार... दिल्ली की जनता की जो पीड़ा है, इस किराये के बढ़ने से जो उनकी जेब पर जो बोझ पड़ रहा है, उससे कोई सम्बन्ध नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। तो सी.एम. साहब ने बहुत बढ़िया प्रस्ताव रखा कि भई, इसको आधा–आधा बांट लेते हैं। 50 परसेन्ट आप भी हिस्सेदार हैं और 50 परसेन्ट हम भी हैं और अगर बार–बार ऑपरेशन लॉस की बात कर रहे हैं तो फिर मेट्रो हमारे हवाले कर दें। हम इसको एक बढ़िया तरीके से चलाके और बिना फेयर बढ़ाकर, क्योंकि मुझसे मीडिया वालों ने भी सवाल किया कि भई आपका

प्लान क्या है? तो प्लान वही है कि जिस प्रकार से ढाई साल से अगर बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिये, उसी प्रकार से मैं भी पूरा ये भी आश्वासन दे रहा हूं कि दिल्ली मेट्रो हमारे हवाले कर दें, अगले पांच साल तक भी किराया बढ़ने की नौबत नहीं आयेगी और अभी स्पीकर सर, मैंने आपके सामने पढ़ा कि कैसे मीटिंग कन्वीन कर सकते हैं कोई भी डाईरेक्टर। फिर दुबारा एक किस प्रकार से केन्द्र सरकार काम कर रही है, किस प्रकार से जो हमारे कान्स्टीट्यूशन में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसका बिल्कुल कत्ल कर रही है। एक और चिट्ठी आज यू.डी. सेक्रटरी, जो चेयरमैन हैं, जिसके बारे में बड़ी वकालत कर रहे थे विजेन्द्र गुप्ता जी। उन्होंने चिट्ठी लिखी है ये और किस अधिकार से लिखी है, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आर्टिकल्स के तहत बोर्ड मीटिंग कन्वीन की पॉवर तो सेक्रेटरी को दी गयी है कि सेक्रटरी शेल कन्वीन अ मीटिंग। उसमें उन्होंने लिखा है कि भई ये बोर्ड मीटिंग बुलाने का कोई फायदा नहीं है। किराया तो बढ़ना चाहिए। क्योंकि इट इज द मैटर ऑफ ग्रेव कन्सर्न। ये बिल्कुल गलत है और मुझे वाकई में ये समझ में नहीं आ रहा है कि 50 परसेन्ट की जब हम शेयर की बात करते हैं तो क्या दिल्ली सरकार का काम सिर्फ 50 परसेन्ट शेयर देने का है। उसके अधिकार, ये अगर बोर्ड मीटिंग बुलाने की भी नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि जी, कि 50 परसेन्ट शेयर की कोई वैल्यू इस पूरे सिस्टम में है। विजेन्द्र गुप्ता जी ने कुछ और भी चीजें रखीं की फेज–चार की डिले की जो बातें रखीं, वो भी फिर बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बिना किसी फैक्ट के, बिना तथ्यों के जो मन में आया बोलते रहते हैं। जहां से कुछ सुनीं, वो बोलते रहते हैं। 6 जनवरी, 2017 में कैबिनेट ने फेज–चार का जितना भी स्कीम था, पास किया। कुछ–कुछ कैबिनेट की ऑब्जरवेशन थीं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट की ऑब्जरवेशन थीं। उसके जो जवाब आये और पिछले कुछ महीने से जिस कारण से ये पूरी स्कीम पास नहीं

हो पायी, उसका मेन कारण जीएसटी है। काफी महीनों से सिर्फ जीएसटी की कैलकुलेशन हो रही है कि जीएसटी का क्या इम्पैक्ट होगा और पिछली जो कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें ये प्रस्ताव था, उसमें ये एजेन्डा था लेकिन चूंकि जीएसटी के क्या इम्पैक्ट होगा और स्पीकर सर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जहां ये 50 परसेन्ट की बात करतें हैं, आपको जानके ताज्जुब होगा कि दिल्ली सरकार, अगर हम टैक्सेज की बात करें तो आज टू/थर्ड टैक्सेज का इम्पैक्ट दिल्ली सरकार पर है, सिर्फ वन/थर्ड जो है, वो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पर है। ये सारा जीएसटी की देन है और पिछले कुछ महीनों से जीएसटी के कारण ये सारा कैबिनेट नोट अटका हुआ है।

तो विजेन्द्र गुप्ता जी से निवेदन है कि जीएसटी पर जल्द से जल्द क्लैरिटी लें और जीएसटी और नोटबन्दी जैसे जो एक्सपैरीमैन्ट हमारे देश पर हो रहे हैं, अगर उनकी ताकत है इतनी तो वो ऊपर तक मेसेज पहुंचाएं कि ऐसे एक्सपैरीमैन्ट करना बन्द करें।

अध्यक्ष महोदयः चलो, कन्क्लूड करिए प्लीज। अब कन्क्लूड करिए।

परिवहन मंत्रीः स्पीकर सर, मैं... आप बैठो, बैठो।

अध्यक्ष महोदयः अरे! क्या कमिटमैन्ट लोगे? आप एक कमिटमैन्ट तो दे नहीं पाये।

परिवहन मंत्रीः अगर आपमे ताकत है, आपमें ताकत है तो फेयर रूकवा के दिखाओ। आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। ये पर्ची भी आयी है स्पीकर सर।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, अब विजेन्द्र जी। कैलाश जी, अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

परिवहन मंत्रीः ये चिट्ठी किसीने दी है, स्पीकर सर?

अध्यक्ष महोदयः हां करिए, कन्क्लूड करिए।

परिवहन मंत्रीः इसमें कुछ लिखा है, मैं मर्द का बच्चा हूं चाहता हूं अगर आप भी, ये विजेन्द्र जी के लिए।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है छोड़िए। अब छोड़िए। अब ये गम्भीर चर्चा है इसको वहीं रहने दीजिए। अब कन्क्लूड करिए, कन्क्लूड करिए प्लीज।

परिवहन मंत्रीः स्पीकर सर, ये पूरी चर्चा के बाद ये चीज क्लीयर है कि मेट्रो के जो फेयर है, वो नहीं बढ़ने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है और जो रिजोल्यूशन है और जो चर्चा के बाद, इसमें सिर्फ एक छोटा सा अमेन्डमैन्ट स्पीकर सर, मैं चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि संकल्प को पारित किया जाए तथा संकल्प की पहली पंक्ति में 4 अक्तूबर, 2017 के स्थान पर 9 अक्तूबर, 2017 को प्रतिस्थापति किया जाए, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः माननीय उप मुख्य मंत्री, श्री मनीष सिसोदिया जी।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये शायद देश का या दुनिया का पहला ऐसा सदन होगा जहां सत्ता पक्ष बैठके कह रहा है, हम किराया कम करेंगे और विपक्ष कह रहा है कि हम तो बढ़वाएंगे। ये शायद दुनिया का पहला सदन होगा जहां सत्ता पक्ष कह रहा है कि नहीं जी, हमें तो किराया कम चाहिए। हमें जनता के हित में किराया चाहिए कम चाहिए और विपक्ष कह रहा है नहीं–नहीं जी, हम तो बढ़वाना चाहते हैं, हम तो बढ़वाना चाहते हैं, बढ़वा के रहेंगे और बढ़वाने की शर्त देखिए। कह रहे है कि वो अगर ये कर दोगे तो वो कर देंगे। अभी नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो मुझे लगान फिल्म का

प्लॉट याद आ रहा था जहां पर वो अंग्रेज कहते हैं कि अगर ये वाला क्रिकेट मैच जीत जाओगे तो हम तुम्हारा लगान माफ कर देंगे। तो ये टैक्स का पैसा नहीं हो गया जनता के, अंग्रेजों का लगान हो गया। ऐसे माफ होता है? अरे! दिल्ली की जनता के पैसे से मेट्रो चल रही है और दिल्ली की जनता के लिए चल रही है। जनता चाहती है किराया कम रहे। वक्त की जरूरत है किराया कम रहे। क्योंकि और कोई भी सामान्य व्यक्ति भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समझता है, वो भी कहेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया कम रखो ताकि अधिक से अधिक लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलें और मेट्रो जिसको विजेन्द्र गुप्ता जी भी कह रहे थे, पूरे देश में भारत का गर्व, पूरे देश में, पूरी दुनिया में मेट्रो का नाम है। उसको मैक्सिमम लोग यूज करें और दुनिया भर में एक मॉडल के रूप में सामने आये कि कैसे पब्लिक मेट्रो को यूज करती है, कैसे दिल्ली का मेट्रो एक बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में सामने आया है, इससे लोग सीखें। यह प्रीमियम क्लास मेट्रो सिस्टम थोड़े ही बनाना है देश का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है। अभी किसी हमारे साथी ने बोला, शायद भावना जी ने बोला, किसी ने बोला कि सरकार ने पिछले ढाई साल में मेट्रो के किसी काम में इंटरवीन नहीं किया। जैसे मेट्रो एक एफिशिएंट कम्पनी के रूप में सामने आई है निकल कर, अपनी फंक्शनिंग के प्वाइंट ऑफ व्यू से, मेट्रो आज बनी है तो यहाँ बैठे वालों ने नहीं बनाई, उनसे पहले वालों ने नहीं बनाई, वहां के इंजीनियर्स ने बनाई हैं, वहां के ऑफिसर्स ने चलाया है इसको। उन्होंने इतना एफिशिएंट सिस्टम बनाया है वहां पर! आज गर्व होता है देखकर कि देश की सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बढ़िया नमूना मेट्रो ने पेश किया है, सबसे क्राउडेड इलाकों में, सबसे वीआईपी इलाकों में कैसे जमीन के नीचे से टनल बनाकर मेट्रो निकाल दी गई, इस सब को देख कर गर्व, फख्र महसूस होता है। लेकिन इसको बदनाम किया जा रहा है, इसको लाकर खड़ा किया जा रहा है कि हम तो इसको देश की प्रीमियम

पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्पनी बनाएंगे, यह स्वीकार नहीं है। यह दिल्ली की जनता के पैसे से बनी कम्पनी है और इसलिए नहीं बनी कि किसी के पास 100 रुपये थे, उसने 100 रुपये इनवेस्ट कर दिए इस उम्मीद से कि मैं हजार रुपये कमाया करूंगा। दिल्ली मेट्रो इसलिए नहीं बनाई गई। दिल्ली मेट्रो इसलिए बनाई गई है कि दिल्ली की पब्लिक को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपलब्ध करा सकें और ऐसा उपलब्ध करा सकें कि दिल्ली की जनता यूज भी कर सके। यही मेरे को एक साजिश नजर आ रही है अध्यक्ष महोदय, इसमें। बड़ी वकालत हो रही है बढ़ाना पड़ेगा, ये–ये कारण हैं, ऐसे बढ़ाना चाहिए, यहां अधिकार नहीं है आपको...

... (व्यवधान)

उप मुख्य मंत्रीः आ रहे हैं, आ रहे हैं। तीन हजार पर भी आएंगे। तीन हजार नहीं हो गए, अंग्रेजों का लगान हो गया, अंग्रेज हो गए हो, अंग्रेजों की सरकार की तरह से व्यवहार करोगे दिल्ली की जनता के साथ में। एक बात याद रखियेगा, विजेन्द्र जी, देखिये, एक बात बता रहा हूं, सिक्का जो है ना, सिर्फ हेड–हेड नहीं होता है टेल भी सिक्के में होता है और मौके–मौके की बात है, जिस दिन टेल ऊपर आ जाता है ऐसे ही 66–67 आकर बैठते हैं। फिर यह हेड वाले सब इधर–उधर घूमते रहते हैं। आज हम टेल की बात कर रहे हैं। जब भी आम आदमी की बात आती है; चार कागज जेब से निकाल लाते हैं, ''देखो, यहां लिखा हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता।'' चार कागज इधर वाली जेब से निकाल लेंगे; पर्चे, ''देखो, ऐसे नहीं हो सकता।'' अरे! दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लोगों ने चुन कर भेजा है इस सरकार को। दिल्ली की जनता के लिए कानून बदलने चाहिए, उनकी जरूरत पड़ेगी तो कानून भी बदलेंगे और कानूनों में कहीं कमी होगी, तो उसको भी ठीक करेंगे। हम, कानूनों की गुलाम सरकार नहीं

हैं, हम दिल्ली की जनता की गुलाम सरकार हैं। हम व्यवस्थाओं के गुलाम नहीं हैं। एक सोच चल रही है और खतरनाक, यह कारपोरेट वर्ल्ड उसकी गुलाम सरकारें लेकर आती हैं इस सोच को। उन्हीं सरकारों ने, उन्हीं सोच ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया, कारपोरेट एजुकेशन सिस्टम, कारपोरेट घरानों को और बड़े–बड़े जिसके नहीं थे, उनके भी खुलवा दिए। उन्होंने ही अस्पतालों को बर्बाद करके रख दिया और आज वो ही दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बर्बाद करना चाहते हैं। आज दिल्ली मेट्रो का किराया, जिसको बढ़ाने की साजिश रची जा रही है, आम आदमी की अफोर्डेबिल्टी में, लेकिन ये चाहते हैं कि उसको बढ़ाकर इतना कर दिया जाए, इतना कर दिया जाए कि दिल्ली में ओला, उबेर जैसी कम्पनियों की चांदी हो जाए, लोग सोचने लगें कि मेट्रो से ज्यादा अच्छा है ओला और उबर में जाने लगो और यह होने लगा है। यह साजिश की जड़ें यहां तक फैली हुई हैं। यह होने लगा है। एक मानसिकता है, जाने–अनजाने लोग बहुत सारे लोग इस साजिश में शामिल हो रहे हैं। यह साजिश रची जाती है बार–बार कि जो भी पब्लिक सिस्टम ठीक से चल रहा है, उसको या तो खराब करके इतना बर्बाद कर दो कि लोग कहने लगें कि हमें प्राइवेट सिस्टम चाहिए या उसको इतना महंगा कर दो कि लोग कहने लगें कि उस वाले की जगह तो यह प्राइवेट वाला अच्छा है। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली में जो टैक्सियों का धंधा चल निकला है, ओला, उबर जैसी टैक्सियों का, वो मेट्रो से सस्ता हो जाए, मेट्रो को इतना महँगा कर दिया जाए, यह उस साजिश का हिस्सा है, यह वकालत उसकी वकालत हो रही है अध्यक्ष महोदय। यह सामान्य चीज नहीं है, यह सामान्य बात नहीं है। यह तो बहाना है। यह तो बहाने मारे जा रहे हैं कि कम्पनी को तीन हजार करोड़ रुपये दो, फलाना दो, यह तो सब बहाने हैं। असली साजिश

इस बात की है कि दिल्ली में जो प्राइवेट टैक्सियों की कम्पनियां हैं, उन कम्पनियों का किराया, उन कम्पनियों का जो फेयर होता है, वो मेट्रो से कम दिखने लगे जनता को। मेट्रो का किराया इतना बढ़वा दो कि एक आम आदमी घर से निकले तो वो यह सोचे कि मैं मेट्रो में इतना रुपया खर्च करूँगा, इससे अच्छा तो इस प्राइवेट टैक्सी कम्पनी में चला जाता हूँ। वहां तक लाना चाहते हैं ये और दिल्ली सरकार पूरी तरह से इसके खिलाफ है। नहीं होने देगी अध्यक्ष महोदय, इस बात को। इस साजिश का पर्दाफाश भी करेंगे और इसको सफल भी नहीं होने देंगे, इस तरह की साजिशों को। ये बार–बार बात करते हैं ऐसी कम्पनी, पैसे, यह करो, वो करो, यह कोई साबुन बेचने वाली कम्पनी थोड़े ही है मेट्रो कम्पनी कि साबुन बेचो और प्रॉफिट कमाओ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से किया गया इनवेस्टमैंट है और इनवेस्टमैंट को समझना पड़ेगा। यह दिल्ली के लोगों के भले के लिए किया गया इनवेस्टमैंट है। उनकी जेब पर डाका डालने के लिए किया गया इनवेस्टमैंट नहीं है। वकालत हो रही है; जनता की जेब पर, जनता पहले टैक्स देगी और ऊपर से जीएसटी में रेट पर रेट बढ़ाते चले जाएंगे। 28 परसेंट का रेट करते चले जाएंगे। पहले जनता टैक्स देगी और उसके बाद में फिर अलग से भी देगी तीन हजार करोड़ रुपये, यह दिल्ली सरकार क्या चीज है? यह तो दिल्ली की जनता के ऊपर चीजें हैं ना। पहले उस जनता से टैक्स लेते हैं; कहते हैं, मेट्रो बनाएंगे और फिर कहते हैं, नहीं, नहीं, अब उस मेट्रो को चलाने के लिए हमें तीन हजार करोड़ रुपये दो और दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से, आप क्या करोगे? आप किराया महंगा कर–कर के टैक्सी कम्पनियों को बढ़ावा दोगे दिल्ली में, आपका धंधा है, यह धंधा चलाओगे आप दिल्ली में? हम दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से तीन हजार करोड़ रुपये और दे दें, हर साल सात सौ, आठ सौ करोड़ रुपये दिए हैं उस जनता ने आपको। अब

कह रहे हैं नहीं, नहीं, और दे दो, तीन हजार करोड़ रुपये निकाल कर दे दो और आप टैक्सियों का धंधा चलवाओगे यहां पर। यह नहीं चलने देंगे अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, दो–तीन चीजें यहां रखी थीं। हम भी चाहते हैं कि मेट्रो एफिशिएंट कम्पनी बने, लेकिन एफिशिएंट बनाने के तरीके ये नहीं हैं। सबसे आसान तरीका है, यह तो, मतलब सारी दुनिया में कोई भी खड़े होकर कह देगा कि किराया बढ़ा दो फायदा हो जाएगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, हमने टैक्स में भी दिखाया है कि हमने 12 परसेंट से 5 परसैंट टैक्स किया, टैक्स का कलैक्शन ज्यादा हुआ है। आप ज्यादा टैक्स करोगे, घाटा होगा। कभी भी कलैक्शन नहीं होगा और यही फॉर्मूला यहां पर लागू होता है। यही फॉर्मूला लागू होता है यहां पर कि अगर आप ज्यादा किराया बढ़ाओगे, जनता यूज करना बंद देगी, आपकी कम्पनी घाटे में चली जाएगी। क्यों फिर जीएसटी में टैक्स कम करवा रहे हो बार–बार?

... (व्यवधान)

उप मुख्यमंत्रीः आ रहा हूँ पेट्रोल, डीजल पर भी आऊँगा। अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते हैं कि मैट्रो दुनिया की सबसे एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्पनी बने, जो अपने दम पर चले। बहुत अच्छी बात है। अभी खड़ी तो दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से है। दुनिया भर के लोग इसको देखें कि कितनी एफिशिएंट कम्पनी है। लेकिन अफसोस होता है कि इसको एफिशिएंट बनाने के सुझावों की जगह डीटीसी को बदनाम किया जा रहा है, डीटीसी को गाली दी जा रही है। कहा जा रहा है कि डीटीसी नहीं बनने देंगे। अरे! आपको मैं कहना चाहता हूं कि आज भी डीटीसी मेट्रो से ज्यादा राइडरशिप के साथ चल रही है दिल्ली में। मेट्रो से ज्यादा लोगों को रोजाना ले जाती है, लाती है और हजारों लोग उसमें काम कर

रहे हैं। आप जब कहते हैं डीटीसी नहीं बनने देंगे, आप डीटीसी की बहुत बड़ी टीम को भी गाली दे रहे हैं, डीटीसी कम्पनी को गाली नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, डेढ़ लाख लोग अभी बाहर आए हैं मेट्रो से, पता चला है अभी डेटा, मैं मंत्री से बात कर रहा था, दोनों ने मुझे दिया था, राइडरशिप कम हुई है। ये डेढ़ लाख लोग कहां गए होंगे? घर तो नहीं बैठे होंगे। वो तो सड़कों पर ही आए होंगे, तो इसका मतलब सड़कों पर भीड़ बढ़ानी है। सड़कों पर टैक्सियों की भीड़ बढ़े, सड़कों पर अपनी मोटर साइकिल लेकर लोग निकलें, सड़कों पर लोग अपनी कार लेकर निकलें, यह चाह रहे हो। पॉल्यूशन बढ़े, यह चाह रहे हो। मैं समझता हूं कि जो जिक्र कैलाश जी ने किया मेट्रो को प्रोफिटेबल और एफैक्टिव एफिशिएंट बनाने के बहुत तरीके हैं। सिर्फ किराया बढ़ाने से मेट्रो एफिशिएंट नहीं हो जाएगी, डूब जाएगी अगर किराया बढ़ाएंगे, तो इस वजह से। अगर किराया बढ़ाकर कंपनियां चलती तो बहुत सारी कंपनियां और चल गई होती। आज दिल्ली मेट्रो के पास में इतनी शानदार प्रापर्टीज हैं, इतनी प्राइम लोकेशन्स पर प्रोपर्टीज हैं। हमने बार बार कहा है कि वहां कबूतरों को दे रखी हैं, उसको व्यापारियों को दो, प्रॉफिट मिलेगा। कबूतर उड़ रहे हैं वहां पर। प्राइम लैंड्स को और दुनियां के माडल्स हैं, बात कर रहे हैं, आठ साल से किराया नहीं बढ़ा। अरे! आठ साल क्या, 80 साल भी किराया नहीं बढ़े अगर आप एफिशिएंटली कंपनी को और इस प्रापर्टी को चला लो तो इस प्रापर्टी का ठीक से यूज करो, 80 साल किराया बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप, यूज तो करो। मेट्रो में विज्ञापन हैं, मेट्रो के साइट्स पर विज्ञापन हैं। मेट्रो के पास इतनी प्राइमलैंड प्रापर्टीज हैं उन सबको यूज करो तो वो नहीं करेंगे बस, जनता बेचारी निरीह है। दिमाग नहीं लगाएंगे। ऐफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। कोई ब्रेन नहीं चलेगा, काम। क्या चलेगा जनता के ऊपर? डाका डाल लो। इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ इतने भर नहीं है कि मेट्रो को

एफोर्डेबल बनाना है, प्रोफिट में बनाना है या मेट्रो को एट पार लेकर आना है। इसके तार वहीं तक जुड़े हुए हैं कि बैकडोर से मेट्रो को इतना महंगा कर दो ताकि यहां की प्राइवेट टैक्सी कंपनियां हमें... अध्यक्ष महोदय, एक दो चीजें नेता प्रतिपक्ष ने उठाईं मैं चाहूंगा कि उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र जरूर करूं। कैलाश जी ने उसका किया था थर्ड और फोर्थ फेज का। मतलब दिल्ली की सरकार चाहे हमारी हो या किसी की हो, दिल्ली की जनता तो जनता है दिल्ली की जनता को दूध देने वाली गाय समझ रखा है, दुधारू गाय समझ रखा है। टैक्स से भी ले लो। पहले मेट्रो बनाने के नाम पर उससे पैसा ले लो, फिर आगे चलाने के नाम पर उससे तीन हजार करोड़ मांग लो फिर टैक्स भी वही देगी, प्रोजेक्ट वर्क पर टैक्स भी वही देगी। क्यों अटका थर्ड फेज? क्योंकि दिल्ली की जनता के ऊपर टैक्स की दोहरी मार डाली जा रही है। बोले सेंटर गवर्नमैंट टैक्स में रिबेट में वो नहीं देगी, माफ नहीं करेगी। दिल्ली सरकार मेट्रो के कंस्ट्रक्शन पर टैक्स माफ करके चलती है, ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं देंगे और जैसे ही जीएसटी आया शर्त लगा दी; टू/थर्ड लगा दो, दिल्ली की जनता के ऊपर टू/थर्ड टैक्स लगेगा। हमें दिल्ली की जनता के हित के लिए लड़ना है और हम उसको ऐसे लुटने देने वाले नहीं हैं। हम भी चाहते हैं मेट्रो। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मेट्रो दिल्ली के लिए किए जाने वाला, दिल्ली के भविष्य के लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमैंट है जो आज के लिए नहीं, आज से 20 साल. 50 साल बाद बाद के लिए भी जरूरी है, आज इसलिए करना चाहिए मेट्रो में इन्वेस्टमैंट। मेट्रो में इन्वेस्टमैंट से मनाही नहीं है लेकिन लेफ्ट राइट सेंटर कहीं से भी किसी भी चैनल से कुछ लिख दोगे कागज पर और वो कागज सैक्रोसैंट हो गया, क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आया है। दिल्ली की जनता कोई मायने नहीं रखती, दिल्ली की जनता के इंटरेस्ट कोई मायने नहीं रखते। ऐसे तो नहीं होने देंगे। आपके

यहां से देर हुई है। सेन्ट्रल गवर्नमैंट की वजह से देर हुई है। इन सारी चीजों में नहीं तो 50 परसेंट की साझेदारी है। बोलो, आज 50 परसेंट... 50 परसेंट टैक्स है। मैं आज ही शाम को फाइल पर साइन करने को तैयार हूं। आज भी भेज दूंगा फाइल साइन करके। लेकिन 50 परसेंट! 50 परसेंट करो न। 50 परसेंट की भागीदारी है तो क्यों नये नये नखरे दिखाते हो। वहां पर तो इधर के नखरे, उधर के नखरे की बात चलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इन्होंने कुछ पेट्रोल डीजल का जिक्र किया था। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा डेटा इस सदन के सामने रख दूं। आज का डेटा मेरे पास नहीं है क्योंकि जब ये इश्यू आया था मैंने तीन चार दिन पहले एक रिव्यू लेकर डेटा लिया था। पेट्रोल डीजल के दाम रोज फ्लैक्चुएट करते हैं तो इसको आज का न माना जाए दो तीन दिन पहले का है। पेट्रोल का बेस प्राइस 34 रुपये 36 पैसे है उसके ऊपर केन्द्र सरकार 19 रुपये 48 पैसे की एक्साइज लगाती है। 34 रुपये 36 पैसे के ऊपर 19 रुपये 48 पैसे की एक्साइज है तो ये कुल मिलाकर होता है 53 रुपये 84 पैसे 53.84 इसके ऊपर 27 परसेंट अभी दिल्ली में वैट है यानि 14 रुपये 53 पैसे वैट का क्लेक्शन है और इस तरह से रेट बनता है परसों या तरसों का रेट था। ये 68.37 रुपये कम होने के बाद का। अभी सुनिये, सुनिये ज्यादा इधर उधर गणित मत करिए। गणित में कमजोर हो तुम। मान लो कमजोर हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पेट्रोल की कीमत कम हुई थी, आंखें खोलकर मालूम चल रहा है।

डप मुख्यमंत्रीः कोई नहीं बढ़ाया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बढ़ाया है आपने।

उप मुख्यमंत्रीः अरे! बेकार की बात कर रहे हो आप। ये जुमले और भाषण बाहर के लिए रखा करो, सदन में सच बोला करो।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 2016 में दो परसेंट बढ़ाया। जुलाई 2015 में आपने 5 परसेंट बढ़ाया।

... (व्यवधान)

उप मुख्यमंत्रीः विजेन्द्र गुप्ता जी डेटा में भी आपसे मजबूत रहता हूं और गणित में भी आपसे मजबूत हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ...आप क्या बोल रहे हैं? ...को गुमराह नहीं कर सकते।

उप मुख्यमंत्रीः अरे! जो गुम है और जिसकी कोई राह नही, उसको कोई क्या गुमराह करेगा!

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, कहां आप 2016 की बात कर रहे हो?

उप मुख्यमंत्रीः पहले बताइये मेट्रो का किराया बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए?

... (व्यवधान)

उप मुख्यमंत्रीः गुप्ता जी, शोर मत मचाइये, आप बात कीजिए। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेट्रो का किराया बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बिल्कुल तरीके से बात करेंगे हम। ऐसे नहीं आप पहले पेट्रोल...

उप मुख्यमंत्रीः पहले मेट्रो पर चर्चा हो रही है, मेट्रो का किराया बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? अरे! मेट्रो के किराये पर क्यों नहीं बोलते हो?

जवाब नहीं है। टैक्सी कंपनियां... सब दलाली खाते हो। दिल्ली की जनता को टैक्सी कंपनियों का गुलाम बनाना चाहते हो, नहीं बनाने देंगे आपको। नहीं बनाने देंगे हम, दिल्ली की जनता को टैक्सी कंपनियों का गुलाम। मेट्रो में चलाएंगे अब दिल्ली की जनता को।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप पाँच परसेंट वैट कम करिए।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, बैठिये, प्लीज बैठिये।

उप मुख्यमंत्रीः सुनिये, बैठिये नीचे। आपको कुछ नहीं आता है। आपको सिर्फ शोर मचाना आता है। नीचे बैठिये। जवाब दे रहा हूं मैं आपकी बात का।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप बैठ जाइये। विजेन्द्र जी, मैं कह रहा हूं बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप आराम से नहीं बोल रहे हैं। आप आराम से बोल ही नहीं रहे हैं। आप नीचे बैठ जाइये अब।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदयः वैट का मैंने जवाब दिया था आपको।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे वैट का जवाब नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदयः मैंने जवाब दिया है आपको। ठीक ढ़ंग से जवाब दिया है।

... (व्यवधान)

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इनमें दम नहीं है, जो एक बार भी खड़े होकर कह सकें कि मेट्रो का किराया कम होना चाहिए। मेट्रो का किराया कम हो सके, इनमें दम नहीं है। एक बार तो दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए कि किराया कम होना चाहिए, नहीं कह सकते हो।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः पेट्रोल पर कोई बात नहीं है। आप बैठ जाइये। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, बैठ जाइये।

उप–मुख्यमंत्रीः जब पेट्रोल पर बहस होगी, पेट्रोल पर भी बात करेंगे। दिल पर हाथ रखकर बोलिए मेट्रो का किराया कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दिल पर हाथ रखकर मैं बोलूंगा, दिल पर हाथ रखकर आप बोल दो।

उप–मुख्यमंत्रीः कम होना चाहिए मैं बोल रहा हूं। दिल पर दोनों हाथ रखकर बोल रहा हूं, कम होना चाहिए। बेकार की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मैंने बोल दिया। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा आप सदन को आश्वासन दीजिए के हम किराया नहीं बढ़ने देंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं बताता हूं न। आप खुद कह रहे हैं कंपनी है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः दिल्ली की मेट्रो को बुलेट बना रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं हम दिल्ली को।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि

यहां इन्होंने सदन में यह बात उठाई। पांच परसेंट कम होने की चिट्ठी सेन्ट्रल गवर्नमैंट से आई है। पेट्रोल कोई घर में सप्लाई होने वाली, कोई पाइप लाइन से होने वाली चीज नहीं है जिसका रेट अपने हिसाब से हम लोग इधर उधर कर लें। इस तरह से उसको बाकी राज्यों के हिसाब से भी समकक्ष देखना पड़ता है। आज तो हरियाणा में इनकी सरकार है, वहां पर पांच परसेंट घटायें। उतना सेक्रोसेंट था तो पहले मान जाते न। उत्तर प्रदेश ने घटाये हैं और मैं बता रहा हूं आज भी दिल्ली में हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, आपकी भाजपा शासित सरकारों से कम हैं पैट्रोल और डीजल के दाम, और जिस दिन वो घटा देगें, उससे कम दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। मैं कम करके रखूंगा।

अध्यक्ष महोदयः अब क्या करेगे, बोलिए अब? अब आप बोलो ना किराया कम करवाइए। किराया कम करवाइए। दिल्ली को बचाइए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे तो बोलने दें।

अध्यक्ष महोदयः बोलिए और क्या बोलेगें? मैं सुन चुका हूं। बहुत देर से। ये माइक बंद कर दीजिए।

उप मुख्य मंत्रीः हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदयः आपकी नीयत ठीक नहीं है। आपकी नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने बोल दिया। आप ईमानदारी से... मैं माइक खुलवाता हूं। ईमानदारी से कहिए कि हम जाएंगे, मैट्रो का किराया कम करवाएंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मुझे बोलने से पहले बंद भी करवा दिया।

अध्यक्ष महोदयः बोलिए आप, मैट्रो का किराया कम करवाएंगे?

उप मुख्य मंत्रीः केन्द्र सरकार क्रूड ऑयल के दाम इतने नीचे आ चुके हैं, केन्द्र सरकार कुंडली मारकर बैठी है। क्रूड ऑयल के दाम... तीन गुणा कम हो चुके हैं दाम। क्यों कमाई कर रही है, किसके लिए कमाई कर रही है? सोलह हजार गुणा बड़े–बड़े नेताओं के बच्चों की कम्पनियों को सोलह हजार गुणा फायदा पहुंचाने के लिए है ये। तीन गुणा पैट्रोल के दाम नीचे आ चुके हैं इन्टरनेशनल मार्केट में। उसके बावजूद केन्द्र सरकार कम नहीं कर रही है प्राईज। दो रूपये का झुनझुना पकड़ा कर दिल्ली की जनता को और देश की जनता को बेवकूफ बना रही है। मैं कह रहा हूं आज भी आपके राज्यों से ज्यादा सस्ता है दिल्ली में पैट्रोल और डीजल। और आज लिखकर दे रहा हूं, यहां सदन में स्टेटमैंट दे रहा हूं। यूपी और हरियाणा से सस्ता ही रखेगें, चाहे जैसे भी हो, सस्ता रखेंगे, हमारा वादा है।

अध्यक्ष महोदयः बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री संजीव झाः अभी तीन दिन पहले...

अध्यक्ष महोदयः एक बार इसको कर लें। टी ब्रेक के बाद ले लें प्लीज।

श्री संजीव झाः बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदयः ये एक बार रेजल्यूशन तो पास कर दें।

श्री संजीव झाः ठीक है।

अध्यक्ष महोदयः अब श्री कैलाश गहलोत जी माननीय परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधित संकल्प सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें;

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हॉ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

संशोधित संकल्प पारित हुआ।

... (व्यवधान)

एक सैकेंड, दो मिनट रूक जाइए। देखिए या तो वोटिंग का प्रपोजल चीफ व्हिप से पहले आ जाता, अब ये अब नहीं हो सकता। कुछ नियम भी हैं सदन के। अब टी ब्रेक के लिए आधा घंटे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही आधे घंटे चाय ब्रेक के लिए स्थगित की गयी।) किया गया।

सदन अपराह्न 5.30 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदयः मुझे माननीय उपराज्यपाल महोदय से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में...

श्री संझीव झाः गंभीर विषय है, जो आपके माध्यम से मैं सदन में जानकारी देना चाहता हूं। आज से तीन दिन पहले एक ऑन लाइन पोर्टल में एक रिपोर्ट आयी और उस रिपोर्ट में सनसनीखेज कुछ जानकारियां थी। अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, एक मिनट... एक मिनट... मुझे कंप्लीट तो करने दो। अरे! मुझे कंप्लीट तो करने दो... क्योंकि देखो, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहते थे कि ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। आज...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः संजीव जी, भारद्वाज जी, संजीव जी।

... (व्यवधान)

श्री संजीव झाः अध्यक्ष जी, चूंकि ये अत्यंत गंभीर मसला है, अत्यंत गंभीर मसला है, भ्रष्टाचार से बड़ा जुड़ा हुआ मसला है। इसकी जानकारी इस सदन को होनी चाहिए। इस सदन के माध्यम से जनता को होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय चूंकि ये अत्यंत गंभीर मसला है, इसीलिए इसकी जानकारी सदन को होनी चाहिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया बैठें। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया बैठ जाये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया बैठ जायें। सौरभ जी...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्लीज बैठिये। अभी बैठिये, बैठिये। माननीय सदस्य बैठ जायें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य बैठ जायें। माननीय सदस्य बैठ जायें, मैं मांग करता हूं। बैठिये अनिल जी....

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया बैठें? मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया बैठ जायें। प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ....

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण,

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं हाउस छः बजे तक के लिए एडजोर्न कर रहा हूं। मैं हाउस छः बजे तक के लिए एडजोर्न कर रहा हूं।

(सदन की कार्यवाही छः बजे तक के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 6.00 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए ।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, फिर से मैं, चूंकि ये एक अत्यंत गम्भीर विषय है अध्यक्ष महोदय और मुझे लगता है...

अध्यक्ष महोदयः संजीव जी, देखिए मेरी बात सुनिए।

श्री संजीव झाः माननीय सदस्यों को भी पता चलना चाहिए और सदन के जरिए पूरे देश को...

अध्यक्ष महोदयः ये सदन की कार्यवाही को मुझे चला लेने दीजिए।

श्री संजीव झाः नहीं अध्यक्ष महोदय, ये वही मसला है, जो रोबर्ट वडेरा के साथ हुआ था।

अध्यक्ष महोदयः संजीव जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बैठिए।

श्री संजीव झाः मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यही है अध्यक्ष महोदय, कि आज जो अमित शाह के बेटे जय शाह ने जो इस तरह का भ्रष्टाचार किया है, वही भ्रष्टाचार रोबर्ट वडेरा ने किया था, तीन साल तक खूब हंगामा होता रहा, लेकिन मुझे लगता है विधान सभा सदन...

अध्यक्ष महोदयः मुझे इसको करने दीजिए।

श्री संजीव झाः सदन में हमारी आवाज को दबाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदयः मुझे कार्यवाही चलाने दीजिए।

श्री संजीव झाः मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है अगर सदन में भी आवाज को दबाया जाएगा तो आखिर लोग अपनी बात, अपनी आवाज रखें कहाँ और ये भ्रष्टाचार का बड़ा मसला है।

अध्यक्ष महोदयः उप राज्यपाल का विषय बहुत गम्भीर है, मुझे रखने दीजिए सदन में।

श्री संजीव झाः मुझे ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कि इसकी जानकारी, पूरे देश की जनता को पता चलना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री जो हर जगह बड़े–बड़े मंच पे कहते थे न खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज प्रधानमंत्री के नाक के नीचे करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जानकारी नहीं।

अध्यक्ष महोदयः संजीव जी, ऐसे सदन नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं सदन चल पाएगा प्लीज।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, ये जानना माननीय सदस्यों के लिए और इस विधान सभा के जरिए पूरे देश को ये जानना चाहिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार अमित शाह के बेटे जय शाह ने किया है इसमें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी अपनी चेयर पे चलें। अपनी कुर्सी से न उठे।

श्री संजीव झाः ये केवल एक भ्रष्टाचार नहीं है और सबसे मजे की बात है, जब इसको उजागर किया गया तो बड़ी–बड़ी धमकियाँ दी गई। ये लोकतंत्र है, भ्रष्टाचार किसी कम्पनी विशेष के नाम पर नहीं होगा।

श्री अजय दत्तः जो घाटे में चल रही थी 6,230 रुपये का घाटा उसका था, ये कम्पनी एक ही साथ में 80 करोड़ रुपए के फायदे में है। 80 करोड़ रुपए का फायदा, इसका मतलब यहां पर व्यापारों में घोटाले किए। ये जय शाह जो कि अमित शाह का बेटा है, उसकी कम्पनी में 80 करोड़ रुपए कहाँ से आए? ये सरासर घोटाले हैं। हम मांग करते हैं, ये सदन मांग करता

है कि अमित शाह और उनके बेटे के खिलाफ सीबीआई जांच हो, अध्यक्ष जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं फिर माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया करके बैठ जाएं।

श्री संजीव झाः अगर इतने बड़े भ्रष्टाचार की चर्चा अगर सदन में नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा दिल्ली की जनता के साथ, देश की जनता के साथ, इसीलिए एक साल में 16 हजार गुणा मुनाफा!

श्री अजय दत्तः ये कम्पनी टैम्पल इंटरप्राइजिज, इसमें अचानक से मिरैकल हो गए, इसमें अचानक से धन की वर्षा हो गई, अचानक से 16 हजार परसैंट का मुनाफा एक साल में दिखाया गया है, अध्यक्ष जी, यह घोटाले हैं अगर हमारे विधायक ने किसी भी... जरा सी बात पे उनको पकड़ लिया जाता है उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, हमारे विधायकों पर झूठे केस लगाए जाते हैं। यहां पूरे तथ्य सामने हैं इसमें सीबीआई जांच हो, इसके खिलाफ सीबीआई की जांच हो और अमित शाह...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्रवीण जी, अपनी चेयर पे। प्लीज अपनी कुर्सी...

श्री संजीव झाः अगर ये चर्चा नहीं हुई, अमित शाह और...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कुर्सी पर बैठें। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं अपनी, वैल में नहीं आएंगे, नहीं वैल में कोई नहीं आएगा।

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के अनेकों सदस्य वैल में आ गए)

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये माननीय सदस्य बैठें। आप बैठिए प्लीज। बैठिए–बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया अपनी सीट पर बैठें। बैठिए–बैठिए प्लीज, बैठिए। सीट पर जाएं प्लीज। जरनैल जी, मैं खड़ा हूं। चलिए एक बार जरनैल जी, मैं खड़ा हूं। एक बार चलिए अपनी सीट पर।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः राखी बिड़ला जी, सीट पर चलिए अपनी। मैं खड़ा हूं जरा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्रवीण जी, मैं खड़ा हूं जरा, अपनी सीट, नहीं, आप चलिए अपनी सीट पर...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं ऐसा नहीं। सीट पर चलिए प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं सीट पर चलिए। मैं खड़ा हूं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए एक बार बैठिए सीट पर बैठिए, चलिए सब।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, सीट पर जाएं प्लीज, सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बाजपेयी जी, सीट पर जाइए प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना है, कृपया अपनी–अपनी सीट पर जाएं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य कृपया अपनी सीट पर जाएं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जरनैल सिहं, संजीव जी, प्लीज जाइए प्लीज, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई ये ठीक नहीं हो रहा है, आप सीट पर जाइए

प्लीज। कमांडो जी, चलिए प्लीज। आप चलिए तो सही सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजय जी, मैं कह रहा हूं, सीट पर जाइए आप। अरे सीट पर तो जाइए प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये चर्चा करवाने का तरीका नहीं है। आप सीट पर बैठिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सीट पर बैठें। सीट पर जाए प्लीज। आप बैठिए एक बार सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जरनैल जी, सीट पर जाइए। प्लीज, सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः संजीव जी, सदन को मुझे नियम के अनुसार चलाना है, आपके आदेशों के अनुसार नहीं चलाना। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। बैठाइए सबको।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं आश्वासन दे रहा हूं। नहीं–नहीं बैठिए प्लीज संजीव जी बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है एक कंपनी जो घाटे में चल रही है उसे 80 करोड़ रूपये

फायदा और ये पूरी की पूरी भाजपा की जो टीम है इनके मंत्रियों के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे को फायदा पहुंचाया जा रहा है अध्यक्ष जी पूरा फायदा पहुंचाया जा रहा है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं सदस्यों से जाएं वहां पर। जरनैल जी, बाजपेयी जी, चलिए, अपनी सीट पर चलिए। जरनैल जी भारद्वाज जी चलिए सीट पर। मैं प्रार्थना कर रहा हूं माननीय सदस्यों से अपनी सीट पर जाए। ऐसे सदन नहीं चल पाएगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, वो मुझे देखना है कि क्या करना है, आप बैठिए। मुझे इस पर नियम देखना पड़ेगा क्या नियम है, क्या नहीं। मुझे इसमें समय चाहिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, बैठिए, प्लीज बैठिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, जगदीप जी, बुलाइए प्लीज, बुलाइए सबको। बाजपेयी जी, बैठिए प्लीज, जरनैल जी, बैठिए, मुझे समय तो चाहिए ना, नियम वगैरह देखने के लिए। ऐसे नहीं चलता है सदन। सदन को तरीके से चलाना होता है। भई, विषय क्या है? जब तो मैं करूंगा ना। विषय क्या था, मुझे मालूम थोड़ी था। आपने कहा कि कोई गंभीर विषय है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए प्लीज, संजीव जी, बैठिए आप। मैं बाजपेयी जी से, जरनैल जी से बार–बार प्रार्थना कर रहा हूं, बैठ जाए। मैं प्रार्थना कर

रहा हूं, बैठ जाएं। मुझे मजबूर न करें। बैठिए आप जरनैल जी, बैठिए। भारद्वाज जी, मैं हाथ जोड़करकृ. आप बैठिए सीट पर। नहीं... आप सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं सीट पर जाएं। जगदीप जी, बुलाइए, देखिए... मैं, भारद्वाज जी, मुझे नियम देखने पड़ेंगे, क्या कहते हैं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सदन।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, आप बैठिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सदन।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा प्लीज। नितिन जी कुर्सी पर बैठें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अच्छा कुर्सियों पर तो बैठिए पहले, अपनी चेयर पर तो जाइए। ऐसे शोर मचता रहेगा, मैं क्या समझूंगा?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जरनैल जी, अपनी कुर्सी पर जाएं। मैं अब चेतावनी दे रहा हूं चेयर पर जाएं। नहीं, वहीं पर जाकर बात करिए, नहीं वहां जाकर बात करिए अपनी कुर्सी पर जाकर बात करिए प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई नितिन जी, हां, बैठिए प्लीज। एक बार बैठिए, कुर्सी पर जाइए। नहीं ऐसे नहीं चलेगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई सभी अगर ओमप्रकाश की तरह से करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जाइए। तमाशा बन गया ये तो सब। नहीं तो आप बैठेंगे कुर्सी पर। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जरनैल जी, मैं कोई आश्वासन नहीं दूंगा। सदन आपकी डिक्टेशन पर नहीं चलेगा। अब बैठिए आप। बैठिए, चेयर पर बैठिए। जरनैल जी कुर्सी पर बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः संजीव जी, आप चेयर पर बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे लग रहा है, मुझे एक बार बोलने देंगे?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे बोलने भी नहीं देंगे? मैंने बार–बार प्रार्थना की है कुर्सी पर चले जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजय जी, बात करने दीजिए। अब बहुत हो गया। ऐसे नहीं चलेगा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे लग रहा है उपराज्यपाल महोदय के संदेश पर विचार की प्रक्रिया आज पूरी नहीं हो पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, दो मिनट रूक जाइए। मुझे लग रहा है सदन एडजोर्न करना पड़ेगा। यदि सदस्य सहमत हो तो हम सत्र की बैठक की अवधि एक दिन के लिए और बढ़ा सकते हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं नियम देखने बाद करूंगा, नहीं, ऐसे नहीं। 10 अक्तूबर 2017 को माननीय उपराज्यपाल महोदय के संदेश पर सदन में आगे विचार किया जा सकता है। मैं हाउस 6.30 बजे तक के लिए एडजोर्न कर रहा हूं।

सदन अपराह्न 6.30 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

(सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा हंगामा एवं प्ले कार्ड दिखाए गए।)

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब देखिए, दो बार मैं एडजॉर्न कर चुका हूं। बैठिए प्लीज। फोल्ड करिए इसको फोल्ड करिए। बैठिए। बैठ जाइए। प्लीज

बाजपेयी जी, बैठ जाइए। मैं दो बार, देखिए उपराज्यपाल का विषय मेरे लिए बहुत गम्भीर है। उस पर मुझे चर्चा करवाने दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, बैठिए, प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी, बैठाइए प्लीज जरा। माननीय उपराज्यपाल महोदय के सन्देश पर विचार की प्रक्रिया, मुझे लगता है पूरी नहीं हो पा रही है। यदि सदस्य, जरनैल जी मेरी बात सुन लीजिए। नितिन जी, बात सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः थोड़ी देर नही। यदि सदस्य सहमत हो तो हम सत्र की बैठक की अवधि एक दिन के लिए और बढ़ा रहे हैं तथा दिनांक 10 अक्तूबर, 2017 को...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अरे भई, जो माहौल बन रहा है, इसमें मैं नहीं कर सकता हूं। मुझे भी जाना है अब। 10 अक्तूबर, 2017 को माननीय उपराज्यपाल महोदय के सन्देश पर सदन में आगे विचार किया जा सकता हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;

प्रस्ताव पास हुआ।

तदनुसार सदन की बैठक 10 अक्तूबर, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, फिर मैं दोहरा रहा हूं 2.00 बजे नहीं, 11.00 बजे कल बैठक होगी। लंच की व्यवस्था यहीं रहेगी।

अब सदन की कार्रवाई 10 अक्तूबर, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 10 अक्तूबर, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।.)